केंद्र और राज्य शासन से विज्ञापन के लिए अनुमोदित

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

17 वर्षों से निरंतर....

Website:- www.malwaherald.com

RNI No. MPHIN/2010/33238
dainikmalwaherald@yahoo.com
malwaherald@gmail.com

महाकालेश्वर जी का संध्या काल आरती श्रृंगार दर्शन

मालवा हेराल्ड

सुविचार

जैसा सोचा अगर सब वैसा ही हो जाता,तो फिर जिंदगी और ख्वाब में क्या फर्क रह जाता...

वर्ष : 17 अंक : 07 | उज्जैन, बुधवार 17 जून 2026 | पृष्ठ-8 मूल्य-1 रुपए

न्यूज ब्रीफ

ईरान-अमेरिका समझौते से उर्वरक बाजार को राहत, कीमत होगी कम; आयात की लागत भी घटेगी

नई दिल्ली/ जीएनएस। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता भारत के उर्वरक क्षेत्र के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इसका असर सिर्फ यूरिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डीएपी, एनपीके और अन्य उर्वरकों की लागत पर भी पड़ सकता है। वैश्विक बाजार में पहले ही यूरिया की कीमतों में बड़ी गिरावट दिखने लगी है और अब उम्मीद है कि अन्य उर्वरकों के दाम भी नरम पड़ेंगे। इससे सरकार का उर्वरक सब्सिडी बोझ घट सकता है और उपलब्धता बेहतर हो सकती है। पिछले कुछ महीनों से होर्मुज संकट के कारण वैश्विक उर्वरक बाजार दबाव में था। खाड़ी क्षेत्र से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस, अमोनिया और फास्फोरिक एसिड की आपूर्ति होती है। इनकी कीमत बढ़ने से यूरिया, डीएपी एवं एनपीके जैसे उर्वरकों की लागत तेजी से बढ़ गई थी। भारत पर इसका सीधा असर पड़ रहा था। यूरिया बाजार में बदलाव पहले ही आ चुका है। अप्रैल में भारतीय पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के 25 लाख टन यूरिया आयात टेंडर में कीमतें 935 से 959 डालर प्रति टन तक पहुंच गई थीं। यह सामान्य स्तर से लगभग दोगुनी थीं, लेकिन पिछले सप्ताह नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) के 17 लाख टन यूरिया आयात टेंडर में लगभग 62 लाख टन से अधिक की पेशकश हुई। खास बात है कि कीमतें अप्रैल के मुकाबले लगभग आधी रह गईं, जो वैश्विक बाजार में आपूर्ति का दबाव कम होने का संकेत है। इसका मुख्य कारण चीन का उर्वरक बाजार खुलना है। यूरिया के बाद डीएपी और एनपीके आयात में भी राहत मिल सकती है। डीएपी की कुल जरूरत का 55-60 प्रतिशत हिस्सा आयात करना पड़ता है। फास्फोरिक एसिड, रॉक फास्फेट और अमोनिया जैसे कच्चे माल के लिए भी विदेशों पर निर्भरता है। इनमें से बड़ी मात्रा खाड़ी देशों और उससे जुड़े आपूर्ति नेटवर्क से आती है। ऐसे में समुद्री मार्ग सामान्य होने और आयात लागत घटने से डीएपी एवं एनपीके की उत्पादन लागत भी कम हो सकती है।

पार्टी टूटने की अटकलों के बीच सब चंगा सी दिखाने की कोशिश?

मुंबई/ जीएनएस। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की आहट के बीच शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 22 जून को भी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। यह दिन राज्य विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन होगा। उद्धव ने रविवार को पार्टी के सभी लोकसभा सांसदों की भी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 9 में से 4 सांसद व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए, वहीं बाकी 5 वर्चुअल रूप से जुड़े थे। विधायकों की बैठक नरीमन प्वॉइंट स्थित पार्टी कार्यालय गशिवालय में होगी, जहां उद्धव पार्टी के विधायकों को संबोधित करेंगे। चीफ व्हिप सुनील प्रभु और MLC अनिल परब के हस्ताक्षर वाले पार्टी के सर्कुलर में कहा गया है, शिवसेना UBT लेजिस्लेटिव पार्टी के विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों की बैठक 22 जून को शाम 4 बजे शिवालय में आयोजित की गई है। बैठक का मार्गदर्शन पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे करेंगे। सभी सदस्यों से समय पर उपस्थित रहने का अनुरोध है।÷ इसी बीच, शिंदे सेना के MLC कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि ऑपरेशन टाइगर के तहत शिवसेना UBT से सात सांसदों के साथ बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। जैसे ऑपरेशन से पहले मरीज की जांच होती है, वैसे ही यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। बस तारीख तय होना बाकी है। तुमाके ने कहा कि यह मानसून सत्र से पहले होगा। हमारे लिए सभी विवरण बताया उचित नहीं है, लेकिन यह लगभग तय है कि वे हमारे साथ शामिल होंगे। ये बातचीत एक महीने से चल रही है और अब अंतिम चरण में है। हालांकि, शिवसेना UBT के सासंद संजय राउत ने इन दावों को खारिज कर दिया।

बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाएं और जन-कल्याण के लिए 24 हजार 200 करोड़ रूपये की स्वीकृति

प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलिफेंट और ग्रामों के पुनर्वास संबंधी मुआवजा के लिए 2,381 करोड़ 15 लाख रूपये की स्वीकृति

भोपाल/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। बैठक में मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन-कल्याण को बड़ी रफ्तार देते हुए कुल 24,200 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण सहित कुल 19,472 करोड़ 29 लाख रुपये का पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया गया। राज्य में विश्वस्तरीय सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने और परोपकारी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए %मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 लागू करने के प्रस्ताव पर मंत्रि-परिषद ने 5 सदस्यीय मंत्रि-मण्डल उप समिति का गठन किया है। समिति सभी संबंधित पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। मंत्रि-परिषद ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल पर चलाने का पायलट प्रोजेक्ट भी मंजूर किया गया।

वन्य-प्राणी संरक्षण और संवेदनशील क्षेत्रों के 94 गांवों के विस्थापन व मुआवजे के लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि 2026-2031 के तहत 2 हजार 381 करोड़ 15 लाख रुपये आवंटित किए हैं। सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देते हुए जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक व आवासीय सुविधाओं के लिए 687 करोड़ रुपये और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से रेशम उत्पादन की विभिन्न योजनाओं के लिए 639 करोड़ 25 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

मंत्रि-परिषद द्वारा श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन,औद्योगिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए 531 करोड़ 78 लाख रुपये तथा स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन व ऑडिट व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए स्थानीय निधि संपरीक्षा के संचालन के लिए 492 करोड़ 45 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह सभी निर्णय आगामी पांच वर्षों में मध्यप्रदेश के समग्र, समावेशी और सतत विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी पहल है।

इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की पुनरीक्षित लागत और अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 19 हजार 472 करोड़ 29 लाख रूपये की स्वीकृति- मंत्रि-परिषद ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की मूल लागत 7 हजार 500.80करोड़रूपये में 5 हजार 388.58 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत जोड़कर पुनरीक्षित लागत 12 हजार 889.38 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त उ?द्योग के स्वीकृत मानदंडों के अनुसार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण पीपीपी घटक एवं आंतरिक ऋण के प्रभाव को सम्मिलित करते हुए 6 हजार 582.91 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस तरह कुल 19 हजार 472 करोड़ 29 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतिरिक्त वित्त पोषण में भारत शासन और मध्यप्रदेश शासन द्वारा 1,696 करोड़ 74 लाख रूपये की अतिरिक्त इक्विटी और केन्द्रीय करों के लिए 214 करोड़ 64 लाख रूपये का अतिरिक्त अधीनस्थ ऋण, वित्त पोषण एजेंसी बैंकों से ऋण निधि के विरुद्ध 3,496 करोड़ 15 लाख रूपये का अतिरिक्त पीटीए/आंतरिक ऋण, मध्यप्रदेश शासन से राज्य करों के लिए 656 करोड़ 96 लाख रूपये एवं आईडीसीकी लागत के लिए 518 करोड़ 42 लाख रूपये का अतिरिक्त ऋण शामिल है।

प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलिफेंट और ग्रामों के पुनर्वास संबंधी मुआवजा के लिए 2 हजार 381 करोड़ 15 लाख रूपये की स्वीकृति- मंत्रि-परिषद द्वारा वन विभाग के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलिफेंट और ग्रामों के पुनर्वास के लिए मुआवजा सम्बंधी योजना के सोलहवें केन्द्रीय वित आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक कुल 5 वर्षों तक संचालन के लिए कुल 2 हजार 381 करोड़ 15 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है।

स्वीकृति अनुसार प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलिफेंट (नॉन-रिकरिंग), प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलिफेंट (रिकरिंग) और प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलिफेंट (प्रोजेक्ट एलिफेंट) के लिए एक हजार 131 करोड़ 15 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन तीनों योजनाओं से वन्यप्राणी संरक्षण के वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर बनाई गई प्रबंध योजना का क्रियान्वयन किया जाना है, जिसमें मुख्यतः प्रदेश के टाइगर रिजर्व, कूनो राष्ट्रीय उद्यान तथा गांधीसागर अभयारण्य में वन एवं वन्य-प्राणी सुरक्षा के लिए हैबीटेट सुधार, अग्नि एवं वन सुरक्षा, जल स्त्रोतों का विकास, वन मार्गो का रखरखाव आवश्यक संरचनाओं का निर्माण एवं उनका रखरखाव, हाथियों का प्रबंधन एवं सुरक्षा कार्य, रेस्क्यू सामग्री क्रय, कैम्प निर्माण, दवाईयां क्रय एवं हाथियों के लिए भोजन व्यवस्था आदि कार्य किए जायेंगे।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कसा शिकंजा, हिरासत में लिए अनिल अंबानी ग्रुप के दो पूर्व अधिकारी

नई दिल्ली/ जीएनएस। ईडी ने सोमवार को कहा कि उसने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप (आरएएजी) के ग्रुप एमडी सतीश सेठ और गौतम भाईलाल दोशी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया है और उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया है।

ईडी की जांच में पता चला है कि सतीष सेठ ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सड़क निर्माण प्रोजेक्ट्स से जनता के पैसों की हेराफेरी करने में अहम भूमिका निभाई है।

ईडी ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के पूर्व अधिकारियों को किया गिरफ्तार- गौतम दोशी ने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिसका इस्तेमाल रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड में गड़बड़ी से हुई कमाई को इधर-उधर करने के लिए किया गया।

री-नीट का पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर 1000 से अधिक छात्र से ठगी

नई दिल्ली/ जीएनएस। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने सोमवार को राजस्थान के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो एक अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी का नेटवर्क चला रहे थे। यह नेटवर्क छात्रों और उनके माता-पिता को री-नीट एग्जाम के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झूठा वादा करता था और फिर उनसे पैसे ठगता था।

जांच में सामने आया है कि एक हजार से अधिक छात्रों से ठगी की गई है। पुलिस ने आरोपित जयपुर निवासी सुमेर सिंह मीणा और कोटा के निवासी आकाश मीणा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आईएएनएस के अनुसार, अहमदाबाद पुलिस के संयुक्त आयुक्त (अपराध) शरद सिंघल ने कहा कि री-नीट परीक्षा का कोई प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि आरोपितों ने टेलीग्राम पर बनाए गए ग्रुपों के माध्यम से यह दर्शाया कि उनके पास 21 जून को होने वाली नीट-यूजी की फिर से होने जा रही परीक्षा का प्रश्न पत्र है और इसी के नाम पर उन्होंने छात्र से धन ऐंठा।

उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया चैनलों का इस्तेमाल झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए किया गया और फिर साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। प्रेट्र के अनुसार, आरोपितों के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से लगभग 1.50 करोड़ रुपये के लेन-देन किए जाने की जानकारी मिली है।

जांच में यह भी पाया गया कि आरोपित टेलीग्राम चैनलों और ट्रेड विद कारोल और पंकज भारद्वाज नामक ग्रुपों के जरिये निवेश से संबंधित साइबर धोखाधड़ी में भी शामिल थे। ये ग्रुप लोगों को हाई रिटर्न का वादा करके निवेश करने के लिए लुभाते थे और उनसे ठगी करते थे।

चिंता की बातः मलेरिया के खिलाफ सुरक्षा कवच पर मंडराया संकट

नई दिल्ली/ जीएनएस। मलेरिया - एक ऐसी बीमारी जो सालों से न जाने कितने मासूमों की जिंदगी और परिवारों की खुशियां छीनती आई है। इस जानलेवा बीमारी के खिलाफ जंग में कीटनाशक युक्त मच्छरदानियां (इंसेक्टिसाइड-ट्रीटेड नेट्स - आइटीएन) हमेशा से एक बेहद साधारण, सस्ता और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच रही हैं। लेकिन हाल ही में हुआ एक वैश्विक विश्लेषण हमें खुश होने के साथ-साथ गंभीर रूप से सचेत रहने की चेतावनी दे रहा है।

12 देशों (भारत और चीन सहित एशिया व अफ्रीका के देश) पर हुए अध्ययनों का विश्लेषण बताता है कि यह सुरक्षा कवच अब खतरे में है। मच्छरों में कीटनाशकों के प्रति बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता (रेसिस्टेंस) इस जीवन रक्षक साधन के प्रभाव को कम कर रही है। लाखों जिंदगियों का सहारा आस्ट्रेलिया की जेम्स कुक यूनिवर्सिटी और नाइजीरिया की यूनिवर्सिटी आफ जोस के शोधकर्ता डा. गबेमिनियाई ओटोलोरिन के नेतृत्व में कुल 25 अध्ययनों की बारीकी से जांच की गई।

इसमें 19 अध्ययन मलेरिया के मामलों पर और छह अध्ययन इसके कारण होने वाली मौतों पर आधारित थे। इस विश्लेषण से यह सुखद सच सामने आया कि इन मच्छरदानियों ने मलेरिया को रोकने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।

आंकड़ों की बात करें तो (एशिया में) इन मच्छरदानियों के इस्तेमाल से मलेरिया के मामलों में 68 प्रतिशत की भारी गिरावट आई और मौतों में 18 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। (अफ्रीका में) इसने मलेरिया के मामलों को 29 से 40 प्रतिशत तक कम करने में सफलता पाई। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं हैं, बल्कि उन लाखों चेहरों की मुस्कान हैं जिन्हें इस साधारण से साधन ने जीवनदान दिया है।

प्रियांक खरगे बोले, खुद को पंजीकृत कराए आरएसएस; भागवत ने इसे राजनीति बताया

बेंगलुरु/ जीएनएस। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर संगठन की कानूनी स्थिति और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को एक खुला पत्र लिखकर आरएसएस से खुद को पंजीकृत करने, अपनी संपत्ति, आय-व्यय के स्त्रोतों को सार्वजनिक करने और संवैधानिक जवाबदेही तय करने की मांग की है।

उधर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उनकी इन मांगों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। इंटरनेट मीडिया पर अपना पत्र साझा करते हुए प्रियांक खरगे ने कहा कि देश-विदेश में 60 हजार से अधिक शाखाएं और करोड़ों स्वयंसेवक होने का दावा करने वाले संगठन को पारदर्शिता और कानून का पालन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार, अकेले कर्नाटक में आरएसएस की 4,127 दैनिक शाखाएं और हजारों अन्य कार्यक्रम होते हैं। इतनी बड़ी जनभागीदारी और रूट मार्च जैसे आयोजनों को निजी या अनौपचारिक व्यवस्था नहीं माना जा सकता।

सुदीप बंदोपाध्याय ने पूरी की भाजपा की दशकों पुरानी मुराद, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा

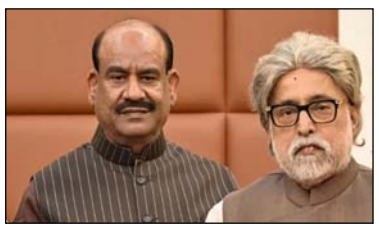

नई दिल्ली/ जीएनएस। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के छह बार के सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय का बागी सांसदों से मिल जाना ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा सकता है। सुदीप बंदोपाध्याय ने बीते दिन रविवार, 14 जून को दूसरे बागी सांसदों के साथ मिलकर स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी में चल रहे संकट के बीच उन्होंने पाला बदल लिया।

ममता का छोड़ा साथ, BJP की मुराद पूरी- 77 वर्षीय बंदोपाध्याय संसद के अनुभवी नेता हैं। पार्टी की चेयरपर्सन 71 वर्षीय ममता बनर्जी से उम्र में बड़े होने के बावजूद, वे दशकों तक उनके सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान, बंदोपाध्याय उन अहम हस्तियों में से एक थे, जिन्हें BJP अपने साथ लाना चाहती थी। इसकी वजह साफ थी कि वे तृणमूल के सबसे मजबूत सांसदों में से एक थे।

सुदीप बंदोपाध्याय ने 1999 में लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) के तौर पर काम किया था और उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं की गहरी जानकारी थी। वे संसद की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह समझते थे। बीजेपी उस दौरान वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हिंदी पट्टी से बाहर अपना विस्तार करने की कोशिश कर रही थी। उनका मानना था कि सुदीप बंदोपाध्याय कोलकाता और बाकी बंगाल में तृणमूल के प्रभाव को कमजोर करने में उनकी मदद कर सकते हैं।

16 महीने बाद G7 में मिले मोदी और ट्रंप, गर्मजोशी से हाथ मिलाया और फिर...

नई दिल्ली/ जीएनएस। जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 16 महीने बाद पहली सार्वजनिक मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और एक-दूसरे का अभिवादन किया। यह मुलाकात वैश्विक कूटनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का विशेष स्वागत किया। मैक्रों ने मोदी को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और दोनों नेताओं के बीच कुछ देर अनौपचारिक बातचीत भी हुई। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप आमने-सामने आए और हाथ मिलाते हुए एक-दूसरे का हालचाल जाना

यह भेंट इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि पिछले 16 महीनों में दोनों नेताओं के बीच कोई प्रत्यक्ष सार्वजनिक मुलाकात नहीं हुई थी। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, रक्षा सहयोग और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर पहले से ही चर्चा चल रही है। हालांकि इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच विशेष बातचीत नहीं हुई, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है।

बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा आयोजित इस जी-7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और फ्रांस के अलावा भारत समेत कई प्रमुख देशों के नेता शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य एजेंडा वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नियमन, मध्य पूर्व की स्थिति और यूक्रेन संकट जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित है।

बताया जा रहा है कि इसके अलावा मोदी और ट्रंप एक दूसरे से अलग से बात करेंगे। 17 जून को दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। जानकारी के अनुसार, मोदी-ट्रंप मुलाकात में भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने, रक्षा क्षेत्र में गहरा सहयोग और ऋण फ्रेमवर्क को मजबूत करने पर विशेष जोर दे सकते हैं।

जनसुनवाई में उमड़ा भरोसा, 109 शिकायतों पर पुलिस कमिश्नर ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और प्रभावी समाधान के लिए आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में मंगलवार को पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह ने नागरिकों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में कुल 109 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें पारिवारिक विवाद, वित्तीय धोखाधड़ी, संपत्ति संबंधी मामले, महिला अपराध और पुलिस कार्रवाई से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं।

जनसुनवाई में सबसे अधिक मामले बेटा-बहू द्वारा प्रताड़ना, पति-पत्नी के विवाद, झूठे लोन, वेतन भुगतान नहीं होने और आपसी पैसों के लेन-देन से जुड़े विवादों के सामने आए। इसके अलावा प्लॉट, मकान और जमीन से संबंधित धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड तथा सुनवाई नहीं होने की शिकायतें भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुईं।

पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कई मामलों में अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया, जबकि कुछ प्रकरणों में दूरभाष के माध्यम से भी तत्काल निर्देश जारी किए गए।

जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) श्री मयंक अवस्थी सहित सभी जोन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं को विस्तार से सुनकर समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए।

पुलिस कमिश्नर ने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि इंदौर पुलिस उनकी सुरक्षा, न्याय और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाएगा और पीड़ितों को समय पर राहत दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही पुलिस द्वारा संचालित मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से पारिवारिक एवं आपसी विवादों में काउंसलिंग कर सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में भी लगातार कार्य किया जा रहा है।

वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंदौर पुलिस ने उप निरीक्षकों को दिया विशेष प्रशिक्षण

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में वीआईपी आगमन एवं विभिन्न महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा उप निरीक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण सत्र में डीसीपी जोन-2 श्री अमन सिंह राठौर एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्रीमती सीमा अलावा ने अधिकारियों को एस्कॉर्ट सुरक्षा अधिकारी की भूमिका और दायित्वों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने वीआईपी आगमन एवं प्रस्थान के दौरान सुरक्षा प्रबंधन, विभिन्न सुरक्षा श्रेणियों के अनुसार पुलिस बल की तैनाती तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान किए।

अधिकारियों को कारकेड व्यवस्था, मार्ग सुरक्षा, पायलट एवं एस्कॉर्ट वाहनों की भूमिका, आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया तथा विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में सुरक्षा व्यवस्थाओं के व्यावहारिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया, ताकि वीआईपी ड्यूटी के दौरान किसी भी स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।

इस अवसर पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें, जिससे विशिष्ट अतिथियों के आगमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुचारू और निर्बाध रूप से संचालित हो सके।

इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा समय-समय पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना तथा कानून-व्यवस्था एवं नागरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाना है।

डिफेंस मन्युफेक्चरिंग में आत्मनिर्भरता नारा नहीं बल्कि एक मिशन है- संभागायुक्त

संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में डिफेंस मन्युफेक्चरिंग में आत्मनिर्भरता विषय पर कार्यशाला आयोजित

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्यप्रदेश इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एवं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के संयुक्त प्रयासों से डिफेंस मन्युफेक्चरिंग आत्मनिर्भरता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एम.पी.आई.डी.सी. के कार्यकारी संचालक श्री हिमांशु प्रजापति, एयर मॉर्शल श्री विभास पाण्डे, मेजर जनरल श्री एस.के. श्रीवास्तव, कर्नल श्री राकेश सिसोदिया एवं इण्डो जर्मन टूल रूम के मैनेजर श्री अनिल, डॉ. डी.वी. रोटेला उपस्थित थे। जनरल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के डेप्यूटी डायरेक्टर श्री अनिल राय वर्चुअली जुड़े। कार्यशाला में एम.एस.एम.ई., स्टार्टअप, शिक्षा संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट, औद्योगिक संगठन आदि के 100 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कार्यशाला में रक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम में स्टेज-3 लेवल का कन्सलटेशन प्रोग्राम है, जिसमें मध्यप्रदेश को को-लीड स्टेट चुना गया है।

कार्यशाला में संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह प्रयास है कि भारत रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करें। वर्तमान परिदृश्य में यह अतिआवश्यक भी हो जाता है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में उपस्थित सभी को जानना आवश्यक है कि किस प्रकार स्वदेशी निर्माताओं की भूमिका रक्षा उत्पाद में बढ़ाई जा सके। जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इको सिस्टम एवं सुविधाएं जिसमें कि शासकीय अनुदान भी शामिल है, वो यहां उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस इको सिस्टम का उपयोग रक्षा उत्पादों के विनिर्माण हेतु किस प्रकार किया जा सकता है, यह जरूरी है। भारत में निर्मित हर उत्पाद ग्लोबल स्टैंडर्ड का होना अत्यन्त आवश्यक है तभी उनका उपयोग किया जा सकता है। डॉ. सुदाम खाड़े ने कहा कि कार्यशाला में शामिल सभी प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त सुझावों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जायेगा जिससे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हो सके।

कार्यशाला में श्री अनिल कुमार राय द्वारा प्रजेंटेशन के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा रक्षा उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की जानकारी दी गई। साथ ही डिफेंस मन्युफेक्चरिंग में एम.एस.एम.ई., स्टार्टअप, शिक्षा संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि संस्थानों की भूमिका को सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार द्वारा डिफेंस उत्पादन को बढ़ाएं जाने संबंधी नीतियों तथा सृजन पोर्टल, निर्यात आदि के संबंध में जानकारी भी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि भारत सरकार लगातार डिफेंस उत्पादों हेतु आर एण्ड डी एवं टेस्टिंग फेसिलिटी का देश भर में विस्तार कर रही है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में एम.पी.आई.डी.सी. के कार्यकारी संचालक श्री हिमांशु प्रजापति द्वारा मध्यप्रदेश में रक्षा विनिर्माण हेतु, इको सिस्टम एवं मध्यप्रदेश शासन की रक्षा उत्पाद हेतु विशेष नीति की जानकारी दी गई।

लाल किला मैदान में गूंजा जनजातीय अस्मिता का स्वर, जनजाति समागम 2026 में उठी संवैधानिक अधिकारों की मांग

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आयोजित जनजाति समागम 2026 देश के जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा, आस्था और संवैधानिक अधिकारों का विराट मंच बनकर उभरा। देशभर के 500 से अधिक जनजातीय समुदायों से आए लाखों लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा, लोकनृत्य, लोकगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत का प्रदर्शन किया।

समागम के दौरान राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों से विशाल शोभायात्राएं निकाली गईं, जो लाल किला मैदान पहुंचकर एक भव्य जनसमूह में परिवर्तित हुईं। लेह-लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक के जनजातीय प्रतिनिधियों ने अपनी सांस्कृतिक विविधता और एकता का परिचय दिया।

कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज भारत की सांस्कृतिक आत्मा का अभिन्न हिस्सा है और यह समागम आने वाले वर्षों में जनजातीय समाज के महाकुंभ के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने जनजातीय समुदायों की प्रकृति-पूजा, जल-जंगल-जमीन के संरक्षण और सामुदायिक जीवन शैली को भारत की सांस्कृतिक धरोहर बताया।

समागम में वक्ताओं ने जनजातीय समाज को प्रकृति और संस्कृति का संरक्षक बताते हुए कहा कि विश्व आज पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे समय में जनजातीय जीवन-दर्शन टिकाऊ विकास का मार्ग दिखाता है। जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह आयोजन केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की लंबे समय से लंबित मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास है।

मंच ने अनुसूचित जनजाति की स्पष्ट वैधानिक परिभाषा निर्धारित करने, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में आवश्यक संशोधन करने तथा जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग दोहराई। प्रतिनिधियों ने कहा कि जनजातीय पहचान केवल संवैधानिक सूची का विषय नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, परंपरा और सामुदायिक जीवन से जुड़ा प्रश्न है।

कार्यक्रम में बताया गया कि इस विषय को लेकर वर्षों से देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर जनजातीय समाज की प्रमुख मांगों से अवगत कराया है।

समागम का समापन जनजातीय समाज की सांस्कृतिक अस्मिता, परंपरागत आस्था, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ठोस पहल किए जाने के आह्वान के साथ हुआ।

ब्रिक्स कृषि सम्मेलन में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 48 पुलिसकर्मी सम्मानित

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह ने ब्रिक्स कृषि सम्मेलन-2026 के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित कुल 48 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। यह सम्मान पुलिस कमिश्नरेट द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पुरस्कार कार्यक्रम के तहत प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन करना है। पलासिया स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि बेहतर पुलिसिंग और नागरिक सुरक्षा के लिए समर्पित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। उन्होंने सम्मानित पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी समर्पण और दक्षता के साथ कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की। सम्मानित अधिकारियों और कर्मचारियों ने ब्रिक्स कृषि सम्मेलन-2026 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेट्रोलिंग, एरिया डॉमिनेशन तथा वीआईपी आवागमन की व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक संचालित किया था। एयरपोर्ट सुरक्षा एवं रिसेप्शन व्यवस्था, होटल शेरटन और होटल मेरियट में सुरक्षा प्रबंधन तथा यातायात नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा शहर में विभिन्न आपराधिक मामलों के सफल खुलासे और प्रभावी कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। थाना भंवरकुआ क्षेत्र में अंतरराज्यीय लूट गिरोह का पर्दाफाश कर 33 मोबाइल, एक लैपटॉप और करीब 50 लाख रुपये का माल बरामद करने वाली टीम के सदस्यों को सम्मानित किया गया। वहीं थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में महिला से मंगलसूत्र छीनने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग चार लाख रुपये का माल बरामद करने वाले पुलिसकर्मियों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) श्री आर.के. सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सम्मानित पुलिसकर्मियों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी।

स्कूल चले हम अभियान के तहत बाल विनय मंदिर पहुंचे कलेक्टर

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत कलेक्टर श्री शिवम वर्मा आज शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बाल विनय मंदिर पहुँचे। यहाँ उन्होंने नवप्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत किया। बच्चों से सीधा संवाद किया और उन्हें स्कूल बैग, वाटर बॉटल सहित अन्य जरूरी सामग्री वितरित की। उन्होंने बच्चों को उनके शैक्षणिक जीवन की नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में कलेक्टर श्री वर्मा ने विद्यार्थियों से खुलकर चर्चा की और उन्हें सफलता, नेतृत्व क्षमता, कला, करियर निर्माण तथा बदलती तकनीक के साथ स्वयं को निरंतर अपडेट रखने के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया।

संवाद के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल अकादमिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि प्रभावी संवाद कौशल (कम्युनिकेशन स्किल) और नेतृत्व क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने साथ काम करने वाले लोगों के लक्ष्य, उनकी आवश्यकताओं और उनकी सोच को समझकर उन्हें प्रेरित कर सके तथा सही दिशा दिखा सके।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि स्कूल केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं है, बल्कि यह जीवन के अनेक महत्वपूर्ण कौशल सीखने का मंच भी है। मित्रों, शिक्षकों और सहपाठियों के साथ संवाद करते हुए बच्चों में आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति क्षमता, टीमवर्क और नेतृत्व जैसे गुण विकसित होते हैं, जो आगे चलकर उनके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कलेक्टर श्री वर्मा ने कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के महत्व पर विशेष बल देते हुए कहा कि समाज में अक्सर इन गतिविधियों को केवल सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के रूप में देखा जाता है, जबकि वर्तमान समय में ये उत्कृष्ट करियर विकल्प के रूप में भी उभरकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कला के विभिन्न माध्यम व्यक्ति की संवेदनशीलता, रचनात्मकता और सोच को विकसित करते हैं तथा मानसिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि किसी क्षेत्र में रुचि हो तो उसे पूरे समर्पण और ईमानदारी के साथ अपनाना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन और लंबे समय तक लगातार मेहनत करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और हर उपलब्धि के पीछे कठोर परिश्रम छिपा होता है।

महू पहुंची पंजाब की पंच तीर्थ यात्रा, भाजपा नेताओं ने किया भव्य स्वागत

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। भारतीय जनता पार्टी पंजाब द्वारा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थ स्थलों की यात्रा के तहत निकला श्रद्धालुओं का जत्था सोमवार को महू पहुंचा। बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में यात्रा का भव्य स्वागत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट और भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा सहित पार्टी पदाधिकारियों ने किया।

भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने बताया कि 14 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित यह पंच तीर्थ यात्रा बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर के जीवन से जुड़े पांच प्रमुख स्थलों के दर्शन कराएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन तीर्थ स्थलों का व्यापक विकास किया गया है और उनके ऐतिहासिक एवं सामाजिक महत्व को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

यात्रा के दौरान श्रद्धालु महू स्थित जन्मभूमि, नागपुर की दीक्षाभूमि, मुंबई की चैत्यभूमि, दिल्ली स्थित महापरिनिर्वाण स्थल तथा वर्चुअल शिक्षा भूमि (लंदन) से जुड़े केंद्रों का दर्शन करेंगे। ये सभी स्थल डॉ. अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और सामाजिक न्याय के लिए किए गए उनके योगदान के प्रतीक हैं।

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस अधिकारी सुचाराम लथर, उपाध्यक्ष संजीव अटवाल और यात्रा प्रभारी मनोज चंदेल के नेतृत्व में लगभग 150 श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हैं। सुचाराम लथर ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक बाबा साहेब का संदेश पहुंचाना और उनके प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता व्यक्त करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार बाबा साहेब से जुड़े सभी पंच तीर्थ स्थलों को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान और सम्मान मिला है।

कार्यक्रम में भाजपा नेता शैलेष गिरजे, राधेश्याम यादव, पीयूष गोयल, महेश बागड़ी, सुभाष पाटीदार सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

काम दिलाने के बहाने महिला के चांदी के गहने हड़पने वाला आरोपी गिरफ्तार

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मजदूरी दिलाने का झांसा देकर एक महिला के करीब 500 ग्राम चांदी के आभूषण हड़पने वाले आरोपी को चंदन नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गए चांदी के आभूषण और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आरोपी की गिरफ्तारी 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर संभव हो सकी।

पुलिस के अनुसार 12 जून की सुबह खजराना चौराहे पर मजदूरी की तलाश में खड़ी एक महिला के पास एक युवक पहुंचा और उसे चंदन नगर क्षेत्र के आगे स्थित एक जैन मंदिर में खाना बनाने का काम दिलाने का प्रस्ताव दिया। आरोपी ने महिला को प्रतिदिन 600 रुपये मजदूरी मिलने का भरोसा दिलाया और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर साथ ले गया।

आरोपी महिला को पहले सराफा क्षेत्र और बाद में ग्राम सिंहासा ले गया। वहां उसने महिला को बताया कि मंदिर में गहने पहनकर काम करने की अनुमति नहीं है, इसलिए उसे अपने आभूषण उतारकर देने होंगे। महिला ने भरोसा कर अपने चांदी के आभूषण आरोपी को सौंप दिए। इसके बाद आरोपी मंदिर में बात करने का कहकर मौके से फरार हो गया।

घटना की सूचना मिलने पर चंदन नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस उपायुक्त जोन-4 श्री सुनील मेहता के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने महिला द्वारा बताए गए मार्ग पर लगे करीब 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। तकनीकी जांच और फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में आरोपी जितेंद्र राठौर (32), निवासी कृष्ण बाग कॉलोनी एवं वर्तमान निवासी संस्कृति रॉयल बाग, राऊ ने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से लगभग 500 ग्राम चांदी के कड़े तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। पुलिस आरोपी से अन्य संभावित वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है।

महामहिम राष्ट्रपति के ओंकारेश्वर आगमन के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था परिवर्तित रहेगी

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 18 जून को ओंकारेश्वर आएंगी। इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ओंकारेश्वर में 17 से 19 जून को दोपहर 12 बजे तक यातायात व्यवस्था परिवर्तित रहेगी।

भारी वाहन डायवर्जन व्यवस्था- सुरक्षित आवागमन एवं यातायात के दबाव को कम करने के उदेश्य से इन्दौर इच्छापुर मार्ग पर समस्त प्रकार के भारी माल वाहक वाहनों का रूट डायवर्जन निम्नानुसार रहेगा।

तेजाजी नगर डायवर्जन- इन्दौर से खण्डवा आने वाले भारी वाहन तेजाजी नगर से महु मानपुर धामनोद, खरगोन होते हुये भीकनगांव, देशगावं, खण्डवा आ सकेगें।

सिमरोल डायवर्जन - इन्दौर से खण्डवा आने वाले भारी वाहन सिमरोल से मण्डलेश्वर कसरावद खरगोन भीकनगांव देशगांव, खण्डवा आ सकेंगे।

बड़वाह डायवर्जन - इन्दौर की ओर से खण्डवा आने वाले भारी वाहन बड़वाह से मण्डलेश्वर कसरावद, खरगोन होते हुये भीकनगांव, देशगांव, खण्डवा आ सकेगें।

गदेशगांव डायवर्जन - खण्डवा से इन्दौर की ओर जाने वाले भारी वाहन भीकनगांव खरगोन कसरावद होते हुये इन्दौर जा सकेंगे।

मण्डलेश्वर - मण्डलेश्वर से कसरावद, खलघाट होते हुये इन्दौर जा सकेंगे।

मध्यम एवं छोटे वाहन डायवर्जन व्यवस्था- महामहिम राष्ट्रपति की सुरक्षा को दृष्टि से श्री ओंकारेश्वर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिये दिनांक 18 एवं 19 जून को निम्नानुसार डायर्वजन व्यवस्था रहेगी।

इन्दौर की ओर से आने वाले - इन्दौर की ओर से आने वाले श्रध्दालुओं के मध्यम एवं छोटे वाहन बडवाह, मोरटक्का, सनावद एवं इन्पुन होते हुये ट्रेचिंग ग्राउण्ड एवं ताम्रकर पार्किंग में पार्क कराये जायेगे। पार्किंग से दर्शन स्नान के लिये पैदल जायेंगे।

खण्डवा एवं मूंदी की ओर से आने वाले - खण्डवा एवं मूंदी की ओर से आने वाले श्रध्दालओं के मध्यम एवं छोटे वाहन सनावद एवं इन्पुन होते हुये ट्रेचिंग ग्राउण्ड एवं ताम्रकर पार्किंग में पार्क कराये जायेगे। पार्किंग से दर्शन स्नान के लिये पैदल जायेगे।

बस डायवर्जन व्यवस्था- खण्डवा एवं इन्दौर की ओर से आने वाली श्रद्धालुओं की बसों को मोरटक्का में पार्किंग रहेगी। मोरटक्का से श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन द्वारा लोक परिवहन के माध्यम से ओंकारेश्वर तक पहुंचाया जायेगा।

निगम जनसुनवाई में पहुंचे 74 आवेदन, आयुक्त ने दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 74 आवेदन प्राप्त हुए।

आयुक्त श्री सिंघल ने अपने कक्ष में निगम के सभी अपर आयुक्तों, उपायुक्तों, सहायक आयुक्तों, अधीक्षण यंत्रियों तथा विभाग प्रमुखों की उपस्थिति में जनसुनवाई की। उन्होंने नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं को सीधे सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में राजस्व, मार्केट, भवन अनुज्ञा, स्वास्थ्य, रिमूवल, सीवरेज तथा जनकार्य विभाग सहित अन्य विभागों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। आयुक्त ने प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता से समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को नियमानुसार कार्रवाई कर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने भी आवेदकों की समस्याओं पर आवश्यक जानकारी लेकर निराकरण प्रक्रिया प्रारंभ की।

अफीम नीति 2026-27 पर मंथन, नारकोटिक्स विभाग की अफसरशाही पर बरसे विधायक सकलेचा, तौल के मौके पर ही हो ऑन-द-स्पॉट फैसला

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मालवा-मेवाड़ के लाखों किसानों की तकदीर और देश की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ी आगामी अफीम नीति 2026-27 को लेकर जमीनी स्तर पर हाई-प्रोफाइल मंथन शुरू हो गया है। नीमच के एक निजी होटल में आयोजित अफीम सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक में इस बार केवल रस्मी चर्चा नहीं हुई, बल्कि नारकोटिक्स विभाग की कार्यप्रणाली और नीतिगत विसंगतियों पर सीधे और तीखे प्रहार किए गए। बैठक में मौजूद क्षेत्रीय विधायक व पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने दो टूक लहजे में कहा कि किसान ही इस पूरी व्यवस्था का मुख्य आधार है और उसे परेशान करना पाप है। फैक्ट्रियों या अधिकारियों की मनमानी अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फैक्ट्रियों के बंद कमरों में भाग्य का फैसला गलत- सकलेचा- वरिष्ठ स्तर पर नीतिगत खामियों को उजागर करते हुए विधायक सकलेचा ने नारकोटिक्स विभाग की पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अफीम किसान साल भर खून-पसीना बहाकर फसल तैयार करता है, लेकिन उसके भाग्य का फैसला फैक्ट्रियों के बंद कमरों में छोड़ दिया जाता है। किसानों का माल तीन-तीन दिन तक फैक्ट्रियों में पड़ा रहता है, जिससे पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने विभाग के आला अधिकारियों के सामने मजबूती से मांग रखी कि किसानों के माल का अंतिम निरीक्षण, फाइनल इंस्पेक्शन ऑन-द-स्पॉट यानी तौल के मौके पर ही होना चाहिए और वहीं पर पूरा मामला सेटल किया जाए। फैसले का एकाधिकार केवल फैक्ट्री को सौंप देना पूरी तरह गलत है।

मार्फिन के आधार पर हो पट्टों का वर्गीकरण, 12 आरी का बने विशेष त्रिकोण- बैठक में पिछले वर्ष की अफीम नीति की एक बड़ी विसंगति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। पिछली नीति में न्यूनतम 4.2 मार्फिन के औसत वाले किसान को भी 10 आरी का पट्टा मिला और जो किसान कड़ी मेहनत करके 7.6 जैसी उच्च गुणवत्ता वाली मार्फिन लेकर आया, उसे भी 10 आरी के दायरे में ही सीमित कर दिया गया। यह व्यवस्था ईमानदारी से काम करने वाले किसानों का मनोबल तोड़ने वाली है।

इस व्यवस्था को बदलकर पट्टों को तत्काल तीन श्रेणियों में विभाजित करने का सुझाव दिया गया है। इसके तहत कम मार्फिन वाले पारंपरिक किसानों के लिए 6 आरी, सामान्य औसत वालों के लिए 10 आरी और उच्च मार्फिन देने वाले किसानों के लिए 12 आरी का विशेष पट्टा तय किया जाए। इससे किसानों में गुणवत्ता सुधारने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होगी।

हाईटेक विजन: AI से बढ़ेगा उत्पादन, डिजिटल नापती से थमेगा भ्रष्टाचार- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को अफीम खेती से जोड़ते हुए विधायक सकलेचा ने कहा कि देश को दवाओं के निर्माण के लिए जितने भी केमिकल्स की आवश्यकता है, उनका शत-प्रतिशत उत्पादन हमारे अपने खेतों में होना चाहिए। इसके लिए अफीम के पट्टों की संख्या को वर्तमान 1 लाख से बढ़ाकर सीधे 2 लाख तक ले जाने की जरूरत है।

तकनीकी बदलावों को लेकर उन्होंने सुझाव दिया कि अफीम की खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश तुरंत शुरू किया जाना चाहिए, जिससे फसलों की बीमारियों पर समय रहते काबू पाकर कुल उत्पादन में 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने मैन्युअल नापती पर पूर्ण रोक लगाने की वकालत की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सैटेलाइट और जीपीएस आधारित डिजिटल नापती उपलब्ध है, तब भी विभाग पुराना ढर्रा क्यों अपना रहा है? यह जानबूझकर भ्रष्टाचार के बैरियर खड़े करने जैसा है। नापती पूरी तरह डिजिटल होनी चाहिए ताकि इंसानी दखल और गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो सके।

ऑर्गेनिक खेती पर 20व अतिरिक्त बोनस और सामूहिक बीमा का फॉर्मूला- अफीम की फसल में केमिकल फर्टिलाइजर के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकने के लिए एक बड़ा व्यावहारिक सुझाव सामने आया। इसके तहत जो भी किसान पूरी तरह देसी या ऑर्गेनिक पद्धति से अफीम उगाने का लिखित भरोसा देता है, उसे प्रोत्साहन स्वरूप 20 प्रतिशत अतिरिक्त पट्टा दिया जाए, यानी 10 आरी वाले ऑर्गेनिक किसान का पट्टा सीधे 12 आरी का कर दिया जाए। इससे विदेशों पर निर्भरता घटेगी और इंसानी सेहत के लिए सुरक्षित जीवनरक्षक दवाएं बन सकेंगी।

फसल बीमा के पेचीदा मामले पर अफसरशाही को घेरते हुए वरिष्ठ राजनेता ने कहा कि हर साल नीति बदलने के बजाय सरकार को इसके मजबूत क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को सभी 1 लाख अफीम किसानों के लिए एक सामूहिक टेंडर निकालना चाहिए। इस बड़े वॉल्यूम को देखकर बड़ी बीमा कंपनियां खुद आगे आएंगी। यदि किसी आपदा के कारण 200 से 500 किसानों की फसल खराब भी होती है, तो उसका सामूहिक भार 1 लाख किसानों के बड़े पूल पर विभाजित हो जाएगा, जिससे प्रभावित किसानों को तुरंत और बिना परेशानी के मुआवजा मिल सकेगा।

बैठक में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, सांसद सुधीर गुप्ता और नारकोटिक्स विभाग के डीएनसी निखिल गांधी ने भी विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। बैठक के इन सभी क्रांतिकारी और व्यावहारिक सुझावों को संकलित कर अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली भेजा जा रहा है।

फसल क्षति होने पर पीडित किसान को 56 से अधिक राशि स्वीकृत

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड नीमच श्री पराग जैन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग 6(4) के तहत फसल में आग लगने के कारण 50 हजार 550 रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। एसडीएम नीमच द्वारा दारू निवासी किसान दीपक, दिनेश पिता रमेशचंद्र, चांदीबाई बेवा रमेशचंद्र की ग्राम सेमार्डा में सर्वे नम्बर 132 रकबा 3.02 हे. में से रकबा 2.00 हे. पर गेहूं की फसल बोई गई थी, जिसमें अज्ञात कारण से आग लगने के कारण लगभग 1.25 हे. रकबे के गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। पीडित कृषक दिनेश पिता रमेशचंद्र, चांदीबाई बेवा रमेशचंद्र को रकबा 2.00 हे. में से 1.95 हे. गेहूँ की फसल में आग लगने से नुकसानी होने पर फसल क्षति अनुदान हेतु 50 प्रतिशत से अधिक सिंचित फसल क्षति होने पर 29000/- प्रति हेक्टेयर के मान से 56550 रूपये कृषक खातेदार दीपक, दिनेश पिता रमेशचंद्र, चांदीबाई बेवा रमेशचंद्र को अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है।

मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए दावे आपत्ति 25 जून तक आमंत्रित

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सचिव म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 का द्वितीय संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया हैं । संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावा आपत्ति केन्द्र पर दावे आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 25 जून 2026 को अपरान्ह 03:00 बजे तक नियत की गई हैं । अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच ने बताया, कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र के समस्त मतदाता संबंधित ग्राम पंचायत पर तथा नगरीय क्षेत्र के समस्त मतदाता नगरीय निकाय के वार्ड के मतदान केन्द्रों पर जाकर अपने नाम की जांच प्रारूप मतदाता सूची 2026 में कर सकते हैं।

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला प्रभारी माजिद खान लाला ने बैठक ली

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मंशा अनुसार माजिद खान लाला (उज्जैन) को मंदसौर जिले का नया संगठन प्रभारी नियुक्त किया गया है। जिला प्रभारी माजिद खान लाला ने जिला कांग्रेस कार्यालय, पर बैठक लेकर जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता से राय शुमारी की, प्रभारी ने कहा कि असम चुनाव में आलिम के कहने के बाद भी अल्पसंख्यक ने कांग्रेस को वोट किया, उन्होंने कहा वरिष्ठ नेता भी अल्पसंख्यक नेताओं का भरपूर साथ दे,और कहा कि संगठन सर्जन के तहत अल्पसंख्यक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। मीनाक्षी जी के बारे में भी उनके द्वारा सीट चोरी की घटना होना बताई । बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, संगठन मंत्री अजय लोढ़ा, शहर ब्लॉक अध्यक्ष इष्टा भाचावत, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष विकास दशोरा नगर पालिका नेता रफत पजामी और एस आई आर प्रभारी राजेंद्र सेठिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख,युवक कांग्रेस अध्यक्ष दुर्गेश पटेल,पूर्व ब्लाक अध्यक्ष युनुस मेव सहित कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी कार्यकर्ता प्रोग्राम मै उपस्थित रहे कार्यक्रम का संचालन अनीश मंसूरी जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग ने किया।

नीमच में 21 जून को होने वाली NEET पुनः परीक्षा की तैयारियां पूर्ण, प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

21 जून को दो केंद्रों पर होगी परीक्षा , नीमच के दो केंद्रों पर 926 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन रविवार, 21 जून 2026 को दोपहर 0200 बजे से सायं 0515 बजे तक जिले के दो परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समयानुसार किया जाएगा। परीक्षा केन्द्र श्री सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय, नीमच में 456 परीक्षार्थी ,दोपहर 0200 से सायं 0515 बजे तक परीक्षा में शामिल होंगे। स्वामी विवेकानंद पी.जी.कॉलेज नीमच,में 470 परीक्षार्थी दोपहर 0200 से सायं 0515 बजे तक इस तरह कुल 926 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में नीट परीक्षा की सभी आवश्यक प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है।

कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने अधिकारियों की बैठक में मंगलवार को तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में एसपी श्री राजेश व्यास, एडीएम श्री बीएस कलेश, केंद्राध्यक्ष डॉ.प्रशांत मिश्रा, श्री रामकुमार पेसिया, नगर समन्वयक श्री प्रियदर्शन गर्ग, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में निर्देश दिए गये है, कि परीक्षा केंद्रों पर अधीक्षण यंत्री, म.प्र.वि.वि.कं.लि.नीमच द्वारा निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

एम्बुलेंस व्यवस्था-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 21 जून को दोनों केंद्रों पर मय चिकित्सा स्टॉफ एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी।

फायर ब्रिगेड एवं पेयजल- मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा आपातकालनी स्थिति से निपटने हेतु फायर ब्रिगेड एवं पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी।

यातायात व्यवस्था-थाना प्रभारी, यातायात थाना नीमच द्वारा परीक्षा केंद्रों पर यातायात सुचारू रखा जाएगा।

इस परीक्षा में नगर समन्वयक श्री प्रियदर्शन गर्ग ने बताया, कि 21 जून को परीक्षार्थियों का केंद्रों पर प्रवेश प्रात 11 बजे से प्रारंभ होगा और दोपहर 1.30 बजे तक ही प्रवेश का अंतिम समय रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षार्थियों को एक पासपोर्ट साईज एवं एक पोस्ट कार्ड साईज फोटो तथा परिचय पत्र लाना अनिवार्य रहेगा। परीक्षार्थी कोई भी प्रतिबंधित सामग्री लेकर केंद्र पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। परीक्षार्थियों को केवल पारदर्शी पानी की बोटल के साथ प्रवेश अनुमत रहेगा।

परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश पृथक व्यवस्था केंद्र पर महिला एवं पुरुष परीक्षार्थियों के प्रवेश की पृथक-पृथक प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सम्मानजनक फ्रिस्किंग महिला परीक्षार्थियों की सम्मानजनक फ्रिस्किंग एवं मोबाइल आदि सामग्री रखने की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। फ्रिस्किंग प्रक्रिया महिला एवं पुरुष कर्मचारी द्वारा पृथक-पृथक की जाएगी। आधारभूत सुविधाएं सभी परीक्षा कक्षों में सी.सी.टी.व्ही., पर्याप्त प्रकाश, पंखे व कूलर की व्यवस्था रहेगी। पेयजल की उत्तम व्यवस्था एवं आपात प्रकाश के लिए जनरेटर सेट उपलब्ध रहेगें।

बैठक व्यवस्था प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए एक कुर्सी-टेबल की व्यवस्था रहेगी। एक टेबल पर एक ही परीक्षार्थी बैठकर परीक्षा दे, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

सुरक्षा व्यवस्था केंद्रों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, लाइव सीसीटीवी निगरानी एवं एच.एच.एम.डी. के माध्यम से तलाशी की व्यवस्था की गई है। थ्री-लेयर सुरक्षा लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।

जनसुनवाई में गिरदौडा की बुजुर्ग दम्पति को कलेक्टर ने दिए भरण पोषण दिलाने के निर्देश

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को जनसुनवाई करते हुए 130 आवेदको की समस्याए सुनी और उनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर एसपी श्री राजेश व्यास, जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्री बी.एस.कलेश सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में गिरदौडा के एक बुजुर्ग दम्पति ने भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता दिलाने का अनुरोध किया। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम नीमच को भरण पोषण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर दम्पति को मदद दिलाने के निर्देश दिए है। जनसुनवाई में पिपलिया रूण्डी के कंवरलाल, केशरपुरा कलां के कोमल, खजुरी के रामगोपाल, रतनगढ के राधेश्याम, सारेल्या की माया कुंवर, सिंगोली के केशरीमल जैन, आमली खेडा के राजमल, हवाई पट्टी नीमच के असलम, चौथखेडा के बनवारी, नयागांव के सत्तु धाकड़, आंकली की राधाबाई, उचेड के नेपाल बंजारा, डीकेन के मांगीलाल, रामपुरा की जयश्री, निपानिया की राधाबाई, कलेपुर की भुलीबाई, गिरदौडा की राजकुंवर ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

इसी तरह निपानिया के सज्जनसिह, दिपुखेडी के लालसिह, नीमच सिटी के कैलाश, नयागांव के राजू धाकड, फूलपुरा के रवि शर्मा, रतनगढ की रेखा बैरागी, चौथखेडा के जुझारसिह, यादव मंडी की नीलम, विशन्या के कंवरलाल, नीमच के पुखराज, नयागांव की नंदीबाई, सुवाखेडा के राजेश, फोफलिया के मोहनलाल, कुकडेश्वर के संजय रेगर, जीरन के विनोद राठौर ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन जनसुनवाई में प्रस्तुत किए। जिस पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए।

शिविर मे पहुंच कर योजनाओं का लाभ उठायें - विधायक मालवीय

जनकल्याण शिविर में अतिथियों ने हितग्राहियों को वितरित किया हितलाभ

रतलाम/ प्रवीण व्यास/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के मार्गदर्शन में जिले में जनकल्याणकारी योजनाओं/सेवाओं में पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने हेतु शासन के निर्देशानुसार नगरीय निकाय/विकासखंड मुख्यालय पर 3 दिवसीय जनकल्याण शिविरो का आयोजन किया जा रहा है।

तहसील आलोट में तीन दिवसीय जनकल्याण शिविर का आयोजन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर आलोट विधायक श्री चिंतामणी मालवीय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभप पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि शिविर में पहुंच कर योजनाओं का लाभ उठायें ।

शिविर में नगर परिषद आलोट तथा नगर पालिका ताल के कुल 2642 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने अपनी समस्याओं का निराकरण कराया और शासकीय योजनाओं का लाभ लिया।

शिविर स्थल पर आमजन को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से शासन की योजनाओं एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित करती हुई, प्रदर्शनी भी लगाई गई।

शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने स्मार्ट मीटर के कारण बढ़े हुए बिजली बिलों की जाँच एवं उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु सौंपा ज्ञापन

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर कांग्रेस कमेटी, मंदसौर ने बिजली के स्मार्ट मीटर के कारण बढ़े हुए बिजली बिलों की जाँच एवं उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु एक ज्ञापन म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कार्यपालन यंत्री को सौंपा। ज्ञापन में मांग की है कि मंदसौर शहर में स्मार्ट मीटर लगाए गये है उस दिन से आम उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग की आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है जिससे इन लोगों पर आर्थिक भार बढ़ने से भारी जन आक्रोश है। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान में आपके विभाग के द्वारा कंपनी को दिये गये ठेके के कर्मचारियों द्वारा पुराने मीटरों को बदलकर उनके स्थान पर स्मार्ट मीटर को उपभोक्ताओं की सहमति के बिना लगाया जा रहा है, जबकि शासन द्वारा इन मीटरों को अभी अनिवार्य नहीं किया गया है। इस अवसर पर महेंद्र सिंह गुर्जर,मों. हनीफ शेख,सोमिल नाहटा, मनजीत सिंह टुटेजा, विकास दशोरा, सुरेंद्र कुमावत, रफत पयामी, तरुण खींची, निर्विकार रातड़िया आदि ने सम्बोधित करते हुये कहा की तुरंत बढे हुये बिल वापस लिए जाये जबरदस्ती स्मार्ट मीटर ना लगाये जाये एवं जब चेक मीटर और स्मार्ट मीटर की रीडिंग एक सी हैं तो मीटर क्यों बदले जा रहें हैं पेपर बिल वापस जनता को भेजे जाये क्योंकि कई लोग मोबाइल मे अपना बिल नहीं देख पाते है। शहर ब्लॉक अध्यक्ष इष्टा भाचावत ने ज्ञापन वाचन कर कार्यपालन यंत्री को ज्ञापन दिया गया आभार पंकज जोशी ने माना। इस अवसर पर नरेन्द्र नाहटा, महेन्द्रसिंह गुर्जर, सोमिल नाहटा, इष्टा भाचावत, अजय लोढा, मनजीतसिंह टूटेजा, विकास दशौरा, मंगल गवली, राजेश खिंची, प्रीतम पंचौली, अजय मारू, महेश गुप्ता, उस्मान मंसुरी, अजय सोनी, वकार खान, योगेन्द्र गौड़, फिरोज हुसैन, हनीफ शाह, वसीम खां, सुनिल बसेर, पंकज जोशी, राखी सत्रावाला, नम्रता सत्रावाला, बलवंतसिंह चौहान, अशोक रैकवार, रमेश ब्रिजवानी, मो हनीफ शेख, रफत पयामी, कमलेश सोनी लाला, विजेश मालेचा, अनिल शर्मा, योगिता बैरागी, सुरेन्द्र कुमावत, मो अंसार, मजहर खान, सादिग गौरी, आसिफ छीपा, सुनिता माली, खलील खान, दिलीप देवड़ा, जितेन्द्र सोपरा, मनोहर नाहटा, निर्विकार रातड़िया, सुनिल गुप्ता, सकलैन करार, मुकेश सेठिया, आबिद बेव, रूपल संचेती, मो आसिफ, साबिर कप्तान, मुमताज बी, सुखलाल मीणा, नदीम शाह, आदिल नीलगर, रईस पटवारी, हेमराज खाबिया, माजीद चौधरी सहित बडी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे।

नोट तंत्र में बदलता प्रजातंत्र, लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा : प्रगतिशील लेखक संघ

राजनीतिक उठापटक पर गोष्ठी में वक्ताओं ने जताई चिंता, दल-बदल कानून को और कठोर बनाने की मांग

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में वक्ताओं ने देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, जनप्रतिनिधियों की कथित खरीद-फरोख्त तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

स्वतंत्र पत्रकार असअद अंसारी ने कहा कि देश में प्रजातंत्र धीरे-धीरे नोट तंत्र में बदलता जा रहा है। अब विधायकों और सांसदों के बाकायदा दाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में खुलेआम हार्स ट्रेडिंग पहले कभी देखने को नहीं मिली। नेताओं में नैतिकता नाम की चीज़ लगभग समाप्त हो चुकी है और राजनीति जनसेवा के बजाय एक उद्योग का रूप धारण करती जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विपक्ष इसी प्रकार समाप्त होता गया तो एक-दलीय शासन के माध्यम से तानाशाही की आशंका बढ़ जाएगी। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष कीर्ति नारायण कश्यप ने कहा कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में ज़मीर नाम की चीज़ नहीं बची है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो भूचाल दिखाई दे रहा है, वह भय अथवा लालच का परिणाम प्रतीत होता है। इकाई उपाध्यक्ष डॉ. स्वप्निल ओझा ने कहा कि ऐसा लगने लगा है मानो भारत में डेमोक्रेसी के स्थान पर ऑटोक्रेसी आ गई हो। दिल्ली और पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो घटनाक्रम खुलेआम देखने को मिल रहा है, उसकी निंदा करना प्रत्येक नागरिक और संगठन का दायित्व है। उन्होंने कहा कि अब जनता को अपने वोटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवाज़ उठानी होगी। साथ ही उन्होंने आशंका व्यक्त की कि सत्ता पक्ष दो-तिहाई बहुमत हासिल कर संविधान संशोधन के माध्यम से अपनी मनमानी करना चाहता है।

राज्य कार्यकारिणी सदस्य दिनेश बसेर ने कहा कि वर्तमान राजनीति अवसरवाद का पर्याय बन चुकी है। उपाध्यक्ष प्रकाश गुप्ता ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की तोड़-फोड़ ने प्रजातंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया है। सचिव ब्रजेश आर्य ने कहा कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आर्थिक लाभ के लालच में दल-बदल कर रहे हैं, जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जिस प्रकार दल-विरोधी गतिविधियों पर सदस्यों को छह वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है, उसी प्रकार दल-बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को भी छह वर्षों तक चुनाव लड़ने से वंचित करने का कानून बनाया जाना चाहिए।

इप्टा सचिव हूर बानो सैफी ने कहा कि समय आ गया है जब सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर दल-बदल कानून में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव लाना चाहिए।

कार्यक्रम का संचालन दिनेश बसेर ने किया तथा आभार प्रदर्शन ब्रजेश आर्य ने किया।

अंबा बावड़ी संरक्षण को लेकर सकल हिंदू समाज ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। ग्राम सोनगरी स्थित अंबा बावड़ी के संरक्षण एवं कथित क्षति के मामले को लेकर सकल हिंदू समाज ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि अंबा बावड़ी क्षेत्र हिंदू समाज की प्राचीन आस्था और धार्मिक श्रद्धा का केंद्र रहा है। समाजजनों का आरोप है कि हाल ही में क्षेत्र में स्थित कुछ वृक्षों को काटा गया तथा बावड़ी में मिट्टी भरकर उसके स्वरूप को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि किसी व्यक्ति, संस्था या समिति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही अंबा बावड़ी के संरक्षण, पुनर्स्थापन, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है ओर अपराधियों के विरुद्ध 3 दिवस में कार्यवाही। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि अंबा बावड़ी का धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। इसलिए इसके इतिहास और महत्व के संबंध में सूचना बोर्ड लगाए जाएं तथा आवश्यक होने पर पुरातात्विक और ऐतिहासिक सर्वे भी कराया जाए। विहिप जिला मंत्री हेमंत बुलचंदानी व सकल हिंदू समाज ने प्रशासन से मांग की है कि मामले में शीघ्र कार्रवाई कर क्षेत्र में शांति, सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। उक्त जानकारी विहिप भालोट प्रखंड मंत्री राकेश विश्वकर्मा ने दी।

घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर कोल्ड ड्रिंक पैकेज विक्रय करने पर नापतौल विभाग ने दर्ज किये अपराध प्रकरण

रतलाम/ प्रवीण व्यास/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नियंत्रक नापतौल मध्यप्रदेश भोपाल श्री ब्रजेश सक्सेना एवं कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह द्वारा दिए गए निर्देशो के पालन में निरीक्षक/सहायक नियंत्रक नापतौल विभाग श्री भारत भूषण ने विभागीय अधिनियम और नियमों के अंतर्गत विशेष जांच का पखवाड़ा बनाया गया । पखवाड़ा अंतर्गत दल द्वारा मे. दी फूड गार्डन, महू-नीमच रोड जावरा, मे. होटल श्री रामाय पैलेस महू-नीमच रोड़ जावरा, मे. शिवकृपा रेस्टोरेन्ट महू रोड़ बस स्टेण्ड रतलाम, मे. श्री कृष्णा आईसक्रीम पार्लर एण्ड ज्यूस सेन्टर महू रोड़ बस स्टैण्ड रतलाम, मे. शक्तावत मोबाईल गैलरी (कोल्ड डिंक एवं जनरल सामग्री विक्रेता) महू रोड़ बस स्टैण्ड रतलाम, मे. आभास नमकीन एवं कोल्ड ड्रिंक महू रोड़ बस स्टैण्ड रतलाम, मे. क्रीम एण्ड क्रंच (अमूल उत्पाद विक्रेता) मित्र निवास रोड रतलाम दुकान/संस्था के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ।

उक्त दुकान/संस्था पर विभागीय सुधारक अनुज्ञप्तिधारी श्री मंयक गोयल को ग्राहक बनाकर अलग-अलग ब्राण्ड की कोल्ड ड्रिंक एवं फूट-ड्रिक पैकेज वस्तु को क्रय कराया गया जिसमें उपरोक्त दुकान/सस्था द्वारा कोल्ड ड्रिंक एवं फूट-ड्रिंक के पैकेजों पर कंपनी द्वारा घोषित मूल्य पर 5 रूपयें से 15 रूपये तक अधिक मूल्य पर विक्रय करना पाया गया जो विधिक मापविज्ञान (पैकेज वस्तुएँ) नियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने से प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है।

इसी प्रकार मे. होटल माँ गुरूकृपा रेस्टोरेन्ट महू रोड बस स्टैण्ड रतलाम, मे. आनंद दुध भण्डार (मावा एवं पनीर विक्रेता) महू रोड़ बस स्टैण्ड रतलाम उक्त दुकान/संस्था पर इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण-1, मेकेनिकल तौल उपकरण-1 और लौहा बांट-13 को नियमानुसार निर्धारित समयावधि में विभाग से सत्यापित एवं मुद्रांकित कराया जाना नहीं पाया गया जो विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने से प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। जाचं दल में श्री कैलाशचन्द्र शर्मा, मोहनलाल खेर, गौतमलाल मईडा और मयंक गोयल सम्मिलित थे।

सम्पादकीय

मौजूदा मॉडल ठीक है, लेकिन विकास दर सीमित बनी हुई है

देश में सूक्ष्म वित्त का वाणिज्यिक मॉडल बांग्लादेश ग्रामीण बैंक से प्रेरित है और इसे 'संयुक्त जवाबदेही समूह' मॉडल कहा जाता है। यह मॉडल महिलाओं पर केंद्रित है जिन्हें समूहों में संगठित किया जाता है ताकि वे बिना किसी जमानत (गिरवी) के ऋण प्राप्त कर सकें और साप्ताहिक या मासिक बैठक में व्यापारिक लेन-देन कर सकें। संचालन के विवरण में बदलाव हुए हैं, लेकिन तीन मुख्य तत्व अब तक बरकरार हैं। यानी लेन-देन की नियमितता, महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना, और असुरक्षित ऋण।

यह मॉडल आपूर्ति प्रेरित था और यह सफल रहा तथा इसका तेजी से विस्तार हुआ। समूह बैठकों ने लेनदेन को एकत्रित किया और असुरक्षित ऋण को परस्पर गारंटी प्रदान की। ऋण की राशि और पुनर्भुगतान की किस्तें सभी उधारकर्ताओं के लिए मानक थीं जिन्हें 'लीजिये या छोड़ दीजिये' के आधार पर दिया जाता था। 30-40 महिलाओं के साथ लेनदेन समूह बैठक में 30 मिनट में ही पूरे किए जा सकते थे। ब्याज दरें औसतन सालाना 24 फीसदी से अधिक थीं। परिचालन की लागत नियंत्रण में थी और वृद्धि नए भौगोलिक क्षेत्रों में नए परिवारों की तलाश से आई।

उच्च ब्याज दरों वाला सूक्ष्म वित्त मॉडल कभी भी गरीबी उन्मूलन का मॉडल नहीं था। ये ब्याज दरें कार्यशील पूंजी या ऐसे व्यवसायों के लिए उपयुक्त हैं जिन्हें मामूली निवेश और नियमित नकदी प्रवाह की आवश्यकता होती है। जैसे ही किसी व्यवसाय को बड़े निवेश पूंजी और लंबे पुनर्भुगतान समय की आवश्यकता होती है चक्रवृद्धि प्रभाव ब्याज दरों को बोझिल बना देता है। उदाहरण के लिए यह एक दुधारू पशु को खरीदने के लिए उपयुक्त है लेकिन भूमि, गौशाला और अतिरिक्त श्रम में निवेश के साथ एक छोटा डेरी फार्म स्थापित करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

सूक्ष्म वित्त ने गरीब परिवारों में छिपी हुई क्षमता को राह दी, विशेष रूप से जगह और श्रम की अतिरिक्त क्षमता को। पिछले तीन दशकों में इसने इस कार्य का बखूबी किया है। लेकिन परिदृश्य बदल गया है और यह मॉडल अब आक्रामक वृद्धि के लिए काम नहीं कर रहा है।

यह ध्यान देने योग्य है कि सूक्ष्म वित्त में सभी संकट भौगोलिक रहे हैं। जब भी कोई क्षेत्र संतृप्त हुआ यानी ऋण के लाभार्थी और तलाशने की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई तब संकट उत्पन्न हुआ। प्रत्येक संकट के साथ तीन जाने-पहचाने आरोप भी आए। अत्यधिक ब्याज दरें, जबरन वसूली, और बहु-ऋण यानी एक ही लाभार्थी को कई बार ऋण। जब कई ऋणदाता ग्राहकों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शर्तों पर प्रतिस्पर्धी नहीं होते तो मांग पक्ष पर दबाव बन जाता है।

बीते सालों में नोटबंदी और महामारी ने मॉडल के मूल संचालन नियमों को तोड़ दिया। नोटबंदी ने समूह दायित्व में विश्वास को तोड़ा क्योंकि आवश्यक सेवाओं के व्यवसाय वाले कुछ परिवार (दूध आपूर्ति और खाने-पीने की दुकानें) दूसरों (ब्यूटी पार्लर आदि) की तुलना में संकट से तेजी से उबरे। सूक्ष्म वित्त संस्थानों ने बिना समूह गारंटी पर जोर दिए जो भी उपलब्ध था उसे वसूल लिया और इससे समूह गारंटी और डिफॉल्ट के प्रति शून्य सहिष्णुता का माहौल नहीं रहा। महामारी ने समूह बैठकों की पवित्रता को भंग किया।

इन संस्थानों ने अपनी पेशकशों में बदलाव किए। समूह गारंटी छोड़ दी और शिक्षा ऋण पेश किए तथा संग्रह में डिजिटल हो गए। यह सब किया गया लेकिन महिलाओं और समूह बैठकों से परे मॉडल की मौलिक पुनर्कल्पना किए बिना। हर संकट में वे नियामक और स्व-नियामक संगठन से सुरक्षा उपायों और क्रेडिट ब्यूरो से बेहतर डेटा की अपेक्षा करते हैं। दूसरी ओर ग्राहक रचनात्मक रहे हैं वे अधिक ऋण पाने के लिए कई पहचान बनाने जैसे कदम उठाते हैं।। शुरू में ये संस्थान ग्राहकों से आगे थे लेकिन अब ग्राहक आगे निकल गए हैं।

नीतिगत प्रतिक्रिया सामूहिक सोच की शिकार रही है। इन हितधारक परामर्शों ने मौजूदा मॉडल को ही मजबूत किया। रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू आय का उपयोग सूक्ष्म वित्त को परिभाषित करने और पुनर्भुगतान स्तर तय करने के लिए करना समस्याग्रस्त है क्योंकि जब आय अनौपचारिक स्रोतों से और अस्थिर होती है तो घरेलू आय निर्धारित करना असंभव है और पुनर्भुगतान दायित्व की बाहरी सीमा 50 फीसदी तक तय करना बहुत उदार है।

एक स्वागत योग्य कदम में रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों की परिभाषा बदल दी कि केवल 60 फीसदी ऋण उपरोक्त परिभाषा के अंतर्गत होंगे। शेष 40 फीसदी विविधीकृत किए जा सकते हैं। यह परिभाषा इन संस्थानों की बैलेंस शीट को विविधतापूर्ण बनाने में मदद करती है। हालांकि, सूक्ष्म वित्त संस्थानों का परिचालन मॉडल अपरिवर्तित रहता है, इसलिए वे शेष 40 फीसदी ऋण भी उन्हीं उधारकर्ताओं को और उन्हीं भौगोलिक क्षेत्रों में दे देते हैं जहां उधारकर्ता आय परीक्षण में विफल होते हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संशोधित ऋण-गारंटी योजना की घोषणा एक काल्पनिक समस्या का समाधान करती है। तीन दशकों के ट्रैक रिकॉर्ड वाले और सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के साथ संचालित इस क्षेत्र में ऋण देने के लिए वित्त प्राप्त करना समस्या नहीं होना चाहिए। यदि यह समस्या है तो यह संकेत है कि मांग प्रणाली में दिक्कत है। सूक्ष्म वित्त संस्थानों की बैलेंस शीट के विविधीकरण के जरिये सूक्ष्म वित्त से ऊपर और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से नीचे वाले खंड को संबोधित करना चाहिए।

सहज योग एक अभिनव ध्यान पद्धति

आध्यात्म का अमूल्य ज्ञान भारत की नीव में बसा है भारतीय संस्कृति के प्रत्येक गहन भाव में, यहां की परंपराओं के रीति नीतियों के आदिकालीन इतिहास के,यहां की जीवन शैली के किसी भी ओर छोर में, किसी भी तत्व में झांकने पर अध्यात्म के गहरे बीज दिखाई देते हैं। हजारों वर्ष पहले शुरू हुई सत्य को खोजने की गहन जिज्ञासा आज पल्लवित होकर अपनी समूल विशिष्टताओं के साथ बेहद सरल और सहज पद्धति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। वे सभी लोग जो अपने जीवन का अर्थ खोज रहे हैं वह सब लोग जो बनावटी तथा आयोजक जिंदगी में बंधे नहीं रह सकते। वे सभी लोग जो स्तरीय संतोष से लुभाए नहीं जा सकते तथा जिन्हें नैतिकता और मानवता के मूलभूत गुणों पर सदा से विश्वास रहा है। उन्हें इस उत्क्रांति के विषय में अवश्य ज्ञान होना चाहिये।

हिरणमयेनपात्रेण सत्यस्यापिहितम् मुखम अर्थात सत्य का मुख हिरण्य मय पात्र से ढका हुआ है ईशावास्योपनिषद का यह श्लोक भारतीय अध्यात्म के गूढ़ अर्थ को अपने में समेटे हुए हैं आखिर वह कौन सा सत्य है जिसका मुख स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है

आज सब इसकी अपनी अपनी व्याख्या करते हैं परंतु वास्तव में यह सत्य ईश्वर से संपर्क करने का परम सत्य है जिसे पाने के लिए सांसारिक धर्म के स्वर्ण मायाजाल को तोड़ना और उसके पार उतरना होता है यह हिरण्यमय पात्र सांसारिक भ्रम है जो भौतिक सुख की लालसा में और अधिक और अधिक की मांग करता हुआ समय बिता देता है मानव को भ्रमित करता है परंतु यदि यह भ्रम का पर्दा हट जाए तो सर्वमान्य सत्य प्रकट हो जाता है और वह सत्य है आत्मा में बसे हुए ईश्वर का ज्ञान। जिसे हजारों हजार वर्ष पहले खोजा गया। यह ज्ञान सहज योग के माध्यम से सरलता से साधक को प्राप्त होता है। अर्थात ध्यान के अनुभव सिद्ध प्रयोग के द्वारा साधक के भीतर घटित होता है जिससे कि उसके भीतर की भ्रम की सुवर्ण माया हटती है और आत्म तत्व में बसे हुए ईश्वर का उससे साक्षात्कार होता है इसे ही सहज योग में आत्मसाक्षात्कार कहते हैं सहज योग की प्रणिता श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा सहज की ध्यान पद्धति में साधक को अत्यंत सहजता से दिव्य चेतना से जोड़ दिया जाता है। परम चैतन्य से जुड़ने की यह एकाकारिता वहाँ आती है जहां पर कार्य, कारण और परिणाम तीनों का अनुभव होता है।

रोजगार का सूखा, विकास की हरियाली: युवा भारत की असली तस्वीर क्या?

देश के राजमार्ग विस्तृत हो रहे हैं, हवाई अड्डे आधुनिक बन रहे हैं, डिजिटल अर्थव्यवस्था नए कीर्तिमान गढ़ रही है और भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। लेकिन इस चमकदार विकास के बीच एक प्रश्न लगातार उठ रहा है—यदि प्रगति इतनी तेज़ है, तो रोजगार के अवसर क्यों सिकुड़ रहे हैं? हालिया आँकड़ों के अनुसार, मई 2026 में बेरोजगारी दर 5.5 प्रतिशत तक पहुँचना केवल एक आर्थिक संकेतक नहीं, बल्कि लाखों युवाओं, ग्रामीण परिवारों और शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती चिंता का प्रतिबिंब है। विकास की रफ्तार बढ़ रही है, पर रोजगार उसका साथ नहीं दे पा रहा। यही असंतुलन आज भारत की सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौती बन गया है। क्या रोजगार सृजन के बिना विकास की यह यात्रा सचमुच पूर्ण कही जा सकती है?

इस चुनौती का सबसे गहरा असर ग्रामीण भारत में दिखाई देता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) के अनुसार मई 2026 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है। यह आँकड़ा भले छोटा लगे, पर इसके पीछे की सच्चाई कहीं अधिक गंभीर है। गाँव का युवा अब केवल खेती के सहारे अपना भविष्य नहीं देखता। कृषि आय की अनिश्चितता, बढ़ती लागत और सीमित अवसरों ने उसका भरोसा डगमगा दिया है। वहीं गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार सृजन की गति भी अपेक्षित नहीं रही। नतीजतन, लाखों युवा या तो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं या बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। मनरेगा में बढ़ती मांग इस बात का स्पष्ट संकेत है कि रोजगार संकट अब गाँवों की चौखट तक पहुँच चुका है।

शहरी क्षेत्रों की तस्वीर भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। यद्यपि शहरी बेरोजगारी दर 6.4 प्रतिशत रही, लेकिन रोजगार बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने अवसरों को सीमित कर दिया है। जिन शहरों को कभी संभावनाओं का केंद्र माना जाता था, वहीं आज हजारों योग्य युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। आईटी और सेवा क्षेत्र, जो लंबे समय तक रोजगार वृद्धि के प्रमुख आधार रहे, अब अपेक्षाकृत धीमी गति से अवसर पैदा कर रहे हैं। तकनीकी बदलावों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने भी रोजगार के नए अवसरों को प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप, शहर अब केवल उम्मीदों ही नहीं, बल्कि बढ़ती निराशा के भी केंद्र बनते जा रहे हैं।

सबसे चिंताजनक स्थिति युवाओं की है। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी दर लगभग 15 प्रतिशत (मार्च 2026 में 15.2त्न) तक पहुँचना केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि भविष्य को लेकर बढ़ती असुरक्षा का संकेत है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी लाखों युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। युवा महिलाओं की स्थिति और भी गंभीर है, जिनके लिए अवसर अपेक्षाकृत कम हैं। शिक्षा संस्थानों से निकलने वाले युवाओं के हाथ में डिग्रियाँ तो हैं, लेकिन उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल का अभाव अक्सर उनके मार्ग में बाधा बन जाता है। यही बढ़ता 'स्किल गैप' भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को शक्ति के बजाय चुनौती में बदलने का खतरा पैदा कर रहा है।

इस स्थिति ने स्वाभाविक रूप से सरकार पर भी दबाव बढ़ाया है। पीएम किसान, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं ने रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक पहल की है, लेकिन व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन अब भी अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका है। विनिर्माण क्षेत्र में 'चाइना प्लस वन' रणनीति ने भारत के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं, किंतु उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार में बदलने की प्रक्रिया अभी अधूरी है। विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र वित्तीय चुनौतियों, सीमित ऋण उपलब्धता और अन्य संरचनात्मक बाधाओं से जूझ रहा है, जबकि सबसे अधिक रोजगार सृजन की क्षमता इसी क्षेत्र में निहित है।

वास्तविक आवश्यकता अब ऐसी आर्थिक दृष्टि की है, जिसमें विकास और रोजगार को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक-दूसरे का आधार माना जाए। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, बुनियादी ढाँचे का विस्तार और डिजिटल अर्थव्यवस्था का सशक्तीकरण निस्संदेह महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं, किंतु केवल इनके बल पर रोजगार संकट का स्थायी समाधान संभव नहीं है। ग्रामीण भारत को नई शक्ति और गति देने के लिए फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, हस्तशिल्प, लघु उद्योगों तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापक और लक्षित निवेश की आवश्यकता है। यदि रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे, तो पलायन कम होगा और क्षेत्रीय असमानताएँ भी घटेंगी।

महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है। सुरक्षित कार्य वातावरण, कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर लाखों महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से प्रभावी रूप से जोड़ा जा सकता है। साथ ही शिक्षा संस्थानों और उद्योग जगत के बीच मजबूत एवं व्यावहारिक तालमेल स्थापित करना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ताकि युवाओं को केवल डिग्री नहीं, बल्कि वास्तविक रोजगार योग्य कौशल भी प्राप्त हो सके। रोजगार का प्रश्न केवल नौकरी तक सीमित नहीं है; यह आत्मसम्मान, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय प्रगति से जुड़ा एक गहन एवं व्यापक विषय है। यह आँकड़े वर्तमान साप्ताहिक स्थिति पर आधारित हैं, जो अल्पकालिक बेरोजगारी को अधिक स्पष्ट दिखाते हैं, जबकि सामान्य स्थिति (वार्षिक) में यह दर लगभग 3.2 प्रतिशत रहती है।

दरअसल, यह संकट एक बड़ा अवसर भी है। भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा युवा कार्यबल बनने की क्षमता है, पर यह तभी संपदा बनेगा जब रोजगार को राजनीतिक विमर्श से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय संकल्प बनाया जाए। 5.5 प्रतिशत बेरोजगारी दर चेतावनी देती है कि विकास का अर्थ केवल ऊँची जीडीपी, निवेश या चमकते शहर नहीं हैं। विकास तभी सार्थक है जब वह युवाओं को काम, परिवारों को सुरक्षा और समाज को विश्वास दे। ग्रामीण भारत की उम्मीदों को केंद्र में रखकर रोजगार-प्रधान और समावेशी नीतियाँ अपनाई जाएँ, तभी 'विकसित भारत' का सपना साकार हो सकता है, वरना विकास की चमक के पीछे बेरोजगारी की परछाई और गहरी होती जाएगी।

-प्रो. आरके जैन

संस्कारों और चरित्र से श्रेष्ठ समाज एवं राष्ट्र का निर्माण

प्राचीन काल से लेकर आज तक विचारधाराएँ समाज की मार्गदर्शक रही हैं। उन्होंने मानव सभ्यता को दिशा दी है, उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किया है। व्यक्ति का जीवन उसके विचारों का ही प्रतिफल होता है। जैसा वह सोचता है, वैसा ही बनता जाता है। यही कारण है कि महान चिंतकों और दार्शनिकों के विचार समय और सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों को प्रभावित करते रहे हैं।विचार और सिद्धांत मनुष्य की अंतःप्रज्ञा के दर्पण होते हैं। यही विचार व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं और वही चरित्र आगे चलकर समाज तथा राष्ट्र की दिशा निर्धारित करता है। जब कोई श्रेष्ठ विचार जनमानस तक पहुँचता है और लोग उसे आत्मसात कर लेते हैं, तब वह केवल विचार नहीं रहता, बल्कि एक जनआंदोलन का स्वरूप धारण कर लेता है। इतिहास साक्षी है कि युग परिवर्तन की प्रत्येक बड़ी लहर किसी न किसी महान विचार से ही उत्पन्न हुई है।

प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक इसका सर्वोत्तम उदाहरण हैं। वे रूप-रंग से भले ही आकर्षक नहीं थे, किंतु उनकी विद्वता, मौलिक चिंतन और जनजागरण की क्षमता असाधारण थी। सामान्य जन उन्हें तत्कालीन शासकों से अधिक बुद्धिमान और सम्माननीय मानते थे। उनकी स्वतंत्र विचारधारा तत्कालीन सत्ता को असहज करती थी। परिणामस्वरूप उन्हें मृत्युदंड दिया गया और विषपान के लिए बाध्य किया गया। किंतु सुकरात का शरीर भले समाप्त हो गया, उनके विचार आज भी जीवित हैं और मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह विचारों की अमरता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

इसी प्रकार ने दासप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाते हुए कहा था कि दास भी उतने ही मनुष्य हैं जितने उनके स्वामी। उनके इस विचार ने तत्कालीन अमेरिकी समाज को झकझोर दिया। विरोध इतना तीव्र था कि अंततः उनकी हत्या कर दी गई, किंतु उनके विचारों ने दासप्रथा उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त किया। जनमानस की अंतरात्मा जागृत हुई और मानव अधिकारों की स्थापना का नया अध्याय आरंभ हुआ।

भारत में ने विचारों की शक्ति को अत्यंत सरल शब्दों में व्यक्त किया था–÷हम जो सोचते हैं, वही बन जाते हैं।÷ उनके अनुसार विचार ही व्यक्ति का निर्माण करते हैं। वही उसे महानता की ओर ले जाते हैं अथवा पतन के मार्ग पर धकेलते हैं। विचारों के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। आज विवेकानंद हमारे बीच सशरीर उपस्थित नहीं हैं, किंतु उनके विचार आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भौतिक शरीर नष्ट हो सकता है, परंतु श्रेष्ठ विचार कभी नष्ट नहीं होते।

विचारों की यही अमरता किसी भी तानाशाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इतिहास में अनेक बार सत्ता ने व्यक्तियों को कुचलने का प्रयास किया है, किंतु विचारों को समाप्त नहीं कर सकी। चाहे वह हो या , दोनों के मूल में विचारों की शक्ति ही थी। जब जनमानस जागृत हुआ तो दमन और भय की दीवारें ढह गईं।

-संजीव ठाकुर

कॉकरोच जनता पार्टी की रैली से उठे सवाल

कुछ समय पहले दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा आयोजित रैली ने देश की राजनीति की अन्यथा उदासीन और कमोबेश निष्क्रिय हालत में थोड़ी हलचल पैदा कर दी है। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि सत्तारूढ़ दल किसी भी तरह से जीतने की कोशिश करता है और हारने वाले तुरंत जीतने वाली पार्टी में शामिल हो जाते हैं। संभव है कि सीजेपी 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन के समान बड़ा बदलाव नहीं ला पाए लेकिन इसके प्रति शुरुआती आधिकारिक प्रतिक्रिया बहुत कुछ बता रही है।

एक्स और इंस्टाग्राम में सीजेपी के खातों पर रोक लगाना और कुछ हजार लोगों की रैली में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना। इन कदमों ने जाहिर कर दिया कि हमारा राजनीतिक और सत्ता प्रतिष्ठान, दोनों युवाओं को स्वतंत्र विचारक के रूप में देखने को लेकर असहज हैं। हालांकि रैली बिना किसी बड़ी बाधा के संपन्न हो गई और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे संकेत मिलता है कि अधिकारियों ने अपनी रणनीति को नए सिरे से समायोजित किया ताकि आगे कोई बड़ा विवाद न उत्पन्न हो। पिछले कुछ समय से बार-बार जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

उदाहरण के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए और तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की प्रतिक्रिया को ही ले लें। वर्ष 2019 में एक 19 वर्ष की विद्यार्थी को देशद्रोह का आरोप लगाकार तीन महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया था क्योंकि उसने बेंगलूरु में एक सीएए विरोधी रैली में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए थे।

निस्संदेह वह नारेबाजी गलत थी लेकिन वह युवाओं की अतिउत्साही मूर्खता के अलावा कुछ नहीं थी। वास्तव में आयोजकों ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उसका माइक भी छीन लिया था। लेकिन यह स्पष्ट नहीं? है कि एक अकेले बागी किशोर द्वारा एक आतंकी जैसे देश की तारीफ करने की छिटपुट कार्रवाई भारत की 'संप्रभुता, एकता और अखंडता' को कैसे खतरे में डाल सकती है, जैसा कि देशद्रोह कानून में उल्लिखित है।

सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान राज्य ने युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपने पूरे दमनकारी तंत्र को झोंक दिया। दिसंबर 2019 में पुलिस ने जबरदस्ती जामिया मिलिया विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश किया जिसमें पुस्तकालय भी शामिल था और आंसू गैस व लाठियों का इस्तेमाल करते हुए नागरिकता कानूनों का विरोध कर रहे छात्रों को गिरफ्तार किया। कई और छात्रों को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शनों से घसीटकर ले जाया गया और कुछ को कठोर यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 2020-21 में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन हुआ जिन्हें संसद ने बिना उचित परामर्श के जल्दबाजी में पारित कर दिया था।

अमीर और ताकतवर किसानों ने राजमार्गों को घेरकर छोटे-छोटे शहरनुमा ठिकाने बसा लिए। इससे हजारों यात्रियों को असुविधा हुई। लेकिन गिरफ्तार हुईं बेंगलुरु की 22 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि। उनका अपराध? स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा किसानों के आंदोलन से संबंधित तैयार किए गए कथित टूलकिट की कुछ पंक्तियों को संपादित करना। सरकार ने इस टूलकिट (जो मूलतः प्रदर्शनकारियों के लिए क्या करें और क्या न करें का दस्तावेज था) और दिशा रवि की भूमिका को भारत राज्य के खिलाफ असंतोष फैलाने का देशद्रोह माना। बाद में उन्हें खालिस्तानी अलगाववादियों से भी जोड़ा गया।

ग्रेटा थनबर्ग जो उस समय 17 वर्ष की थीं वो किसानों के विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में ट्वीट करने के कारण भारत सरकार के गुस्से का केंद्र बन गईं। उन्होंने भारतीय कृषि को लेकर अधूरी जानकारी भरी नुकसान न पहुंचा सकने वाली टिप्पणियां की थीं। विदेश मंत्री ने इसे वार्ताओं को बेपटरी करने का विदेशी एजेंडा बताया। जब कैरेबियाई पॉप स्टार रिहाना भी इस ऑनलाइन अभियान में शामिल हुईं तो भारत सरकार ने उनके और कुछअन्य हस्तियों व पत्रकारों के सोशल मीडिया खातों को बंद करने का आदेश दिया।

इन सारी बातों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान आमतौर पर राष्ट्रवाद की प्रतिस्पर्धी कथाओं को असहजता से देखते हैं और चाहते हैं कि युवा वर्ग आज्ञाकारी और सवाल नहीं करने वाला बना रहे। युवाओं में एकरूपता की यह प्राथमिकता राजनीतिक नेतृत्व की उस पुकार से मेल नहीं खाती, जिसमें भारत को महान बनाने के लिए अधिक नवाचार और रचनात्मकता की आवश्यकता बताई जाती है।

ये गुण उन युवाओं में विकसित नहीं हो सकते जिन्हें चुप रहने या बिना सवाल किए आज्ञा पालन करने के लिए मजबूर किया गया हो। नवाचारी सोच के लिए प्रश्न पूछना और खुला मन आवश्यक है। जब दो प्रतिभाशाली छात्रों ने सीबीएसई परीक्षाओं की ऑनलाइन अंकेक्षण प्रणाली में खामियों और चालबाजियों को उजागर किया तो आगे का रास्ता यही था कि उनसे संवाद किया जाए, समस्या को स्वीकार किया जाए और उसे ठीक करने की दिशा में कदम उठाए जाएं बजाय कि उनके उठाए गए मुद्दों को छिपाया जाए।

इसी तरह, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेरोजगार युवाओं पर की गई अनुचित टिप्पणियों के खिलाफ ऑनलाइन हल्के-फुल्के मजाकिया विरोध को आरंभ में ही राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जाने लगा। यह एक गलत आकलन साबित हुआ और परीक्षाओं के पेपर लीक के मुद्दे को उठाने तथा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करने वाला आंदोलन गति पकड़ने लगा।

हालांकि, नवजात सीजेपी आंदोलन से बांग्लादेश और नेपाल में देखे गए कट्टरपंथी शासन परिवर्तनों जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं देखी जानी चाहिए। दोनों पड़ोसी छोटे और अपेक्षाकृत सामाजिक रूप से एकजुट हैं। 17.7 करोड़ लोगों के साथ बांग्लादेश की आबादी उत्तर प्रदेश से भी कम है। वहीं, 2.9 करोड़ की आबादी वाला नेपाल संख्या के हिसाब से भारतीय राज्यों में 16वें स्थान पर आता है। वह असम और पंजाब के बीच में है।

नेपाल और बांग्लादेश में वह विशाल सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक विविधता नहीं है, जिसने भारत में एक सुसंगत राष्ट्रीय युवा आंदोलन के विकास को हमेशा कठिन बनाए रखा है। भारतीय महत्त्वाकांक्षी हो सकते हैं लेकिन उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि उन आकांक्षाओं की सीमा तय करती है, जो व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। सीबीएसई परीक्षाएं और बेरोजगारी मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए अलग-अलग चिंताएं हैं और विरोध की भाषा भारत के सभी युवाओं से मेल नहीं खाती। लेकिन फिलहाल आइए युवाओं की इस शांतिपूर्ण अवज्ञा के इस दुर्लभ दृश्य का आनंद लें।

-धनंजय राजौरा

चिन्ताजनक है महंगी होती दवाइयां, महंगा होता इलाज

भारत आज विकसित राष्ट्र बनने के स्वप्न के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना बार-बार दोहराई जा रही है। बड़े-बड़े बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां और आर्थिक विकास के दावों के बीच एक प्रश्न बार-बार सामने खड़ा हो जाता है-क्या ऐसा भारत वास्तव में विकसित कहलाएगा, जहां एक सामान्य नागरिक बीमारी के कारण कर्ज में डूबने को विवश हो जाए? जहां इलाज और दवाइयों की बढ़ती कीमतें जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय करने लगें? जहां स्वास्थ्य सेवा अधिकार नहीं, बल्कि आर्थिक सामर्थ्य का विषय बन जाए? ऐसे समय में जब महंगाई पहले ही आम आदमी की कमर तोड़ रही है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एन.पी.पी.ए.) द्वारा कुछ जीवनरक्षक दवाओं और टीकों की कीमतों में भारी वृद्धि की अनुमति देना गंभीर चिंता का विषय है। कैंसर की कुछ दवाओं, एंटी-टेटनस सीरम और बच्चों के आवश्यक टीकों की कीमतों में लगभग पचास प्रतिशत तक वृद्धि की स्वीकृति ने लाखों परिवारों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। यह निर्णय केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदना और जनकल्याणकारी शासन की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है।

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में बड़ी संख्या में लोग आज भी अपने इलाज का खर्च अपनी जेब से वहन करते हैं। बीमारी केवल स्वास्थ्य संकट नहीं रह जाती, वह आर्थिक संकट में भी बदल जाती है। एक समय था जब कहा जाता था कि व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के कारण कर्ज में डूबता है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि किसी गंभीर बीमारी का इलाज पूरा परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकता है। कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग या अन्य जटिल बीमारियों का उपचार लाखों रुपये की मांग करता है। ऐसे में यदि जीवनरक्षक दवाइयों की कीमतें भी लगातार बढ़ती रहें तो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवा लगभग असंभव हो जाएगी। एन.पी.पी.ए. ने दवाओं की कीमत बढ़ाने के पीछे उत्पादन लागत में वृद्धि और बाजार में संभावित कमी का तर्क दिया है। उनका कहना है कि यदि दवा कंपनियां लागत भी नहीं निकाल पाएंगी तो वे उत्पादन बंद कर सकती हैं, जिससे मरीजों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। यह तर्क अपनी जगह सही हो सकता है। किसी भी उद्योग को जीवित रहने के लिए उचित लाभ आवश्यक है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जीवनरक्षक दवाओं को सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की तरह देखा जा सकता है? क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभ कमाने की सीमा और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया जाना चाहिए?

स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। दुर्भाग्य से भारत में इन दोनों क्षेत्रों में व्यवसायीकरण का प्रभाव लगातार बढ़ता गया है। निजी अस्पतालों की बढ़ती फीस, महंगे परीक्षण, अनावश्यक जांचें, चिकित्सा उपकरणों का भारी खर्च और अब दवाइयों की बढ़ती कीमतें मिलकर आम नागरिक को असहाय बना रही हैं। चिकित्सा सेवा धीरे-धीरे सेवा के बजाय उद्योग में परिवर्तित होती दिखाई दे रही है। अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र कम और कॉरपोरेट प्रतिष्ठान अधिक प्रतीत होने लगे हैं। रोगी अब मरीज नहीं, बल्कि ग्राहक की तरह देखा जाने लगा है। यह स्थिति केवल आर्थिक असमानता को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि सामाजिक विभाजन को भी गहरा करती है। आज भी देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यतः उन्हीं लोगों को उपलब्ध हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। गरीब व्यक्ति सरकारी अस्पतालों की लंबी कतारों, सीमित संसाधनों और अपर्याप्त सुविधाओं के भरोसे है। अमीर व्यक्ति अत्याधुनिक अस्पतालों और महंगे उपचारों का लाभ उठा सकता है। क्या यही सामाजिक न्याय है? क्या यही वह भारत है जिसकी कल्पना स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक जनहितकारी योजनाएं लागू हुई हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजना ने लाखों लोगों को राहत भी प्रदान की है। जन औषधि केंद्रों की स्थापना ने सस्ती दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में व्याप्त व्यापक विसंगतियां अभी भी बनी हुई हैं। यदि दवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहें और निजी स्वास्थ्य सेवाएं अनियंत्रित होती जाएं, तो इन योजनाओं का प्रभाव सीमित हो जाएगा। वास्तविक चुनौती यह है कि स्वास्थ्य को बाजार की शक्तियों के हवाले छोड़ने के बजाय उसे जनकल्याण के केंद्र में रखा जाए। सरकार का दायित्व केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों पर विशेष नियंत्रण होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। दवा खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आवश्यक दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विशेष सहायता और सब्सिडी भी दे सकती है, ताकि लागत बढ़ने का पूरा बोझ मरीजों पर न पड़े।

इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा और व्यापक होना चाहिए। अनेक गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय परिवार ऐसे हैं जो किसी भी बीमा सुरक्षा से वंचित हैं। गंभीर बीमारी की स्थिति में वे अपनी जीवनभर की जमा पूंजी गंवा देते हैं। स्वास्थ्य बीमा केवल अस्पताल में भर्ती होने तक सीमित न रहे, बल्कि आवश्यक दवाओं और दीर्घकालिक उपचार को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सरकार समय-समय पर दवा कंपनियों की लागत संरचना और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्र समीक्षा कराए। यदि वास्तव में लागत बढ़ी है तो उसका प्रमाण सार्वजनिक होना चाहिए। पारदर्शिता से जनता का विश्वास भी बढ़ेगा और अनावश्यक मूल्यवृद्धि पर भी रोक लगेगी। स्वास्थ्य नीति का मूल उद्देश्य कंपनियों के लाभ और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना होना चाहिए।

वर्ष 2047 का विकसित भारत केवल ऊंची इमारतों, तेज रफ्तार सड़कों और बढ़ती जीडीपी से नहीं बनेगा। उसका वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि वहां का सबसे गरीब नागरिक कितना सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ है। यदि एक किसान, मजदूर, कर्मचारी या निम्न आय वर्ग का व्यक्ति बीमारी के समय सम्मानपूर्वक इलाज प्राप्त नहीं कर सकता, तो विकास के दावे अधूरे रह जाएंगे। आज आवश्यकता केवल दवाइयों की कीमतों पर बहस करने की नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की समग्र समीक्षा करने की है। यह स्वीकार करना होगा कि स्वास्थ्य कोई विलासिता नहीं, बल्कि मौलिक मानवीय अधिकार है। जिस राष्ट्र में नागरिकों को स्वस्थ जीवन का अवसर नहीं मिलता, वहां विकास की चमक भी फीकी पड़ जाती है। समय आ गया है कि सरकार, नीति-निर्माता, चिकित्सा जगत और समाज मिलकर यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सेवा लाभ कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का सशक्त उपकरण बने। अन्यथा विकसित भारत का सपना केवल आंकड़ों में चमकेगा, जबकि आम आदमी बीमारी, कर्ज और असहायता के अंधकार में संघर्ष करता रहेगा। स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ते भारत के सामने यही सबसे बड़ी नैतिक और मानवीय चुनौती है, जिसका समाधान आज ही तलाशना होगा।

-ललित गर्ग

जनसुनवाई में कलेक्टर ने नागरिकों की समस्याएं सुन अधिकारियों को निराकरण के दिये निर्देश

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को कलेक्टर ऋजुराज सिंह ने जनसुनवाई में आये आवेदकों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कलेक्टर सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी, अपर कलेक्टर संजीव जैन सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित थे।

वृद्धा पेंशन शुरू करवाई जाये- जनसुनवाई में आवेदक राधेश्याम पिता रामप्रसाद ने निवासी क्षिप्रासुकल्या ने वृद्धा पेंशन शुरू कराने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर सिंह ने संबंधित अधिकारी को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।

बिजली बिल की राशि कम कराई जाये- जनसुनवाई में आवेदक देवबाई निवासी देवास ने बिजली बिल की राशि कम कराने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर सिंह ने संबंधित अधिकारी को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।

फसल बीमा राशि दिलाई जाये- जनसुनवाई में आवेदक नर्मदाप्रसाद निवासी बावडीखेडा ने फसल बीमा की राशि दिलाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर सिंह ने संबंधित अधिकारी को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।

ऋण माफ किया जाये- जनसुनवाई में आवेदक रामेश्वर पिता सालगराम पाटीदार निवासी इकलेरा माताजी ने सहकारी संस्था से ऋण माफी कराने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर सिंह ने संबंधित अधिकारी को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।

ये आवेदन भी हुए प्राप्त- जनसुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना, जमीन के सीमाकंन, बिजली बिल कम कराने, बीपीएल सूची में नाम जुड़वाने, नामाकंन, बंटवारा, रास्ते पर से अतिक्रमण हटवाने, नालियों की साफ-सफाई करने सहित अन्य आवेदन पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

200 प्रकरण निरस्ती के मामले में सैकड़ों लोग पहुंचे कलेक्टर कार्यालय

शाजापुर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। तहसील में पिछले आठ महीनों के दौरान बड़ी संख्या में राजस्व प्रकरण निरस्त किए गए हैं। इसके विरोध में मंगलवार को किसान, भू-स्वामी, अधिवक्ता, सर्विस प्रोवाइडर और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने एसएलआर अधिकारी अनामिका आर्य को ज्ञापन सौंपते हुए प्रकरणों की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने उज्जैन संभागायुक्त, शाजापुर कलेक्टर और प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग (भोपाल) के नाम एसएलआर अधिकारी अनामिका आर्य को ज्ञापन सौंपा। जिसमें पिछले आठ महीनों के दौरान निरस्त किए गए राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कराने की मांग की गई। साथ ही इसमें पद का दुरूपयोग पाए जाने पर संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि तहसीलदार सुनील पाटिल के कार्यकाल में नामांतरण, फौती नामांतरण, बंटवारा, इंद्राज दुरुस्ती, सीमांकन और भूमि अभिलेख सुधार से जुड़े करीब 200 राजस्व प्रकरण निरस्त किए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे किसान, व्यापारी और अन्य आवेदक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से प्रभावित हुए हैं। साथ ही कई मामलों में पटवारी और संबंधित राजस्व अधिकारियों की सकारात्मक रिपोर्ट होने के बावजूद प्रकरण निरस्त कर दिए गए। यही नहीं पंजीकृत रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क जमा होने के बाद भी नामांतरण के लिए क्रेता और विक्रेता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जा रहा है, जिससे लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पिछले आठ महीनों में निरस्त हुए सभी प्रकरणों की जिला या संभाग स्तर पर विशेष समिति गठित कर पुनः समीक्षा कराई जाए। साथ ही यदि जांच में नियमों के उल्लंघन, लापरवाही या पद के दुरुपयोग के तथ्य सामने आते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

आइए, हम सभी स्वस्थ आदतें अपनाकर अपने लिवर को स्वस्थ बनाएं

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सरोजिनी जेम्स बेक ने जिले में फैटी लिवर रोग के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से एडवायजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि यदि हम आज अपने खान-पान की आदतों और दिनचर्या में सुधार कर लें, तो फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियों से स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। सीएमएचओ ने आग्रह किया है कि फैटी लिवर से बचाव के लिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि या व्यायाम करें, तले-भुने एवं जंक फूड का सेवन कम करें, मीठे पेय पदार्थों से दूरी बनाएं, हरी सब्जियां एवं संतुलित आहार अपनाएं तथा वजन को नियंत्रित रखें। मधुमेह एवं रक्तचाप के मरीज नियमित रूप से अपनी जांच कराते रहें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि लिवर हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो प्रतिदिन अनेक आवश्यक कार्यों का संचालन करता है, दुर्भाग्यवश बदलती जीवनशैली, असंतुलित खान-पान और शारीरिक निष्क्रियता के कारण लिवर की कोशिकाओं में आवश्यकता से अधिक वसा जमा होने लगता है। प्रारंभिक अवस्था में इसके लक्षण प्रायः दिखाई नहीं देते। समय पर पहचान न होने पर यह लिवर में सूजन, सिरोसिस और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है।

बारिश में जहां होता है जलभराव वहां चलाया जा रहा सफाई अभियान

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। आगामी सप्ताह में मानसूनी बारिश शुरू होने की संभावना है। ऐसे में नगर में जलभराव की स्थिति न बने इसके लिए नगर पालिका द्वारा विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है। खासकर जहां हर बार जलभराव की स्थिति बनती है वहां नालों की सफाई की जा रही है ताकि जलनिकासी आसानी से हो सके। साथ ही शहर के प्रमुख नालों और पुलियाओं की भी सफाई की जा रही है ताकि जलभराव से होने वाली समस्याओं को अभी से खत्म किया जा सके। यह अभियान नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम जैन, उपाध्यक्ष पं. संतोष जोशी, स्वास्थ्य समिति सभापति दुष्यंत सोनी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र कुमार दीक्षित के निर्देशन में चलाया जा रहा है। स्वच्छता पर्यवेक्षक संजय पारनछे ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश में जिन क्षेत्रों में जलभराव की समस्या अधिक रहती है वहां जेसीबी मशीनों की मदद से नालों और पुलियाओं की गहन सफाई की जा रही है। इस अभियान के तहत बेरछा रोड स्थित नाला, डासी रोड की पुलिया, कृषि उपज मंडी क्षेत्र, बादशाह पुल, कच्चीवाड़ा नाला, बड़े पुल के नीचे का क्षेत्र, विजय नगर का नाला, वार्ड क्रमांक 24 और वार्ड क्रमांक 28 स्थित काशी नगर के नालों की सफाई की गई है। इसके अलावा अन्य संवेदनशील स्थानों को भी चिन्हित कर वहां सफाई कार्य किया जा रहा है जो आगामी दिनों में भी जारी रहेगा।

हर साल होती है समस्या- मानसून शुरू होते ही कई द्वक्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनती है। जहां से पानी निकासी न होने की वजह से रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इधर मौसम विभाग द्वारा मानसून आने में करीब एक सप्ताह का समय बताया जा रहा है। उसके पहले नपा द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार मानसून के दौरान नागरिकों को जलभराव और गंदे पानी की समस्या नहीं होगी।

कलेक्टर-एसपी के खिलाफ किया अमर्यादित भाषा का प्रयोग, पुलिस ने किया बाहर

किसान की जमीन को दूसरे की जमीन बताने व कार्रवाई न किए जाने पर बिफरा किसान, कलेक्टर कार्यालय परिसर में किया हंगामा

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। कई बार शिकायत करने, आवेदन देने और कार्रवाई न होने पर मंगलवार को जनसुनवाई में आए किसान का सब्र जवाब दे गया और वह बिफर गया, जिसने कलेक्टर-एसपी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और सांठगांठ का आरोप लगाया। किसान द्वारा पुलिसकर्मियों पर भी आरोप लगाए। इस पर पुलिस ने किसान को परिसर से बाहर कर दिया।

पोलायकलां के रहने वाले किसान शरद कुमार शर्मा ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और राजस्व अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी शिकायतों की लगातार अनदेखी की जा रही है और गलत सीमांकन कराया जा रहा है। किसान का दावा है कि उनकी भूमि सर्वे नंबर 4446/3 के सीमांकन में राजस्व अमले ने हेराफेरी की है। जिसकी वह कई बार शिकायत कर चुका है और सीएम हेल्पलाईन पर भी अनगिनत बार शिकायत कर चुका है लेकिन आज तक किसी ने भी ठोस कार्रवाई नहीं की है।

सात सालों से काट रहा चक्कर, अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान- किसान शरद शर्मा ने बताया कि वह साल 2019 से लेकर अब तक कलेक्टर कार्यालय, संबंधित अधिकारियों और सीएम हेल्पलाइन पर करीब 50 से 60 आवेदन दिए हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस राजस्व टीम पर पहले गलत सीमांकन करने का आरोप है, उसी टीम से दोबारा जमीन की नप्ती कराई जा रही है। किसान का आरोप है कि उसकी जमीन को जानबूझकर दूसरे किसान की भूमि बताया जा रहा है और सांठगांठ के चलते गलत सीमांकन किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने और एक नई टीम गठित कर फिर से सीमांकन कराने की मांग की है। लेकिन अधिकारी उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इससे वह बिफर गया और अधिकारियों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। इस पर पुलिसकर्मियों ने उसे वहां से बाहर कर दिया।

इनका कहना है- फरियादी जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों के लिए अमर्यादित और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा था। कानून-व्यवस्था और परिसर की शांति बनाए रखने के लिए उसे कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर भेजा गया।

- अर्जुनसिंह मुजाल्दे, थाना प्रभारी-लालघाटी थाना, शाजापुर

13 साल पुराने मामले में सात साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। मोहन बड़ोदिया पुलिस ने गौवंश संबंधी 13 साल पुराने एक मामले में सात साल से फरार चल रहे एक स्थाई वारंटी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दो दिन उज्जैन में डेरा डाला तब जाकर पुलिस को सफलता मिली। जिसे पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।

इन दिनों पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर जिलेभर में स्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ऑटो चालक सलीम उर्फ मिठिया (40) पिता हबीब खां निवासी ताजपुर हाल मुकाम भैरूनाला उज्जैन की तलाश की जा रही थी। आरोपी पिछले सात वर्षों से फरार था और पुलिस की हर दबिश में अपने ठिकाने से गायब हो जाता था। जिसकी गिरफ्तारी के लिए इस बार पुलिस ने पूरी तैयारी की ओर दो दिन पुलिस टीम ने लगातार उज्जैन में डेरा डाला। मुखबिर से मिली सूचना और साइबर सेल की मदद से आरोपी के ठिकाने का पता लगाया गया। इसके बाद 15 जून को उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को आरोपी को मोहन बड़ोदिया थाने से शाजापुर न्यायालय में पेश करने के लिए रवाना किया गया।

प्रेशर के साथ नगरवासियों को होगी पर्याप्त जलापूर्ति

नपा द्वारा जल वितरण व्यवस्था में किया जा रहा सुधार, इंटेकवेल का भी किया जा रहा निर्माण

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर में जल वितरण व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। इसके लिए पानी की टंकी का निर्माण कर उसकी टेस्टिंग की जा चुकी है। वहीं पाइप लाइन भी बिछाई जा रही है। नपा अधिकारियों की माने तो अगले साल तक पूरे नगर में प्रेशर के साथ पर्याप्त जलापूर्ति की जा सकेगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन नहीं है वहां पर पाइप लाइन डालकर नलों से पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए लगातार कार्य किया रहा है।

अमृत-2 योजना के तहत 15 करोड़ रुपए की लागत से नगर में लालघाटी और नगर पालिका कार्यालय परिसर में पानी की टंकी का निर्माण, नगर में 12 किमी की पाइप लाइन और लालघाटी पर इंटकवेल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से नगर पालिका कार्यालय परिसर में पानी की टंकी का निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है। गत दिनों इस टंकी की टेस्टिंग भी की जा चुकी है। बताया गया कि आगामी एक-डेढ़ माह में इस पानी की टंकी को प्रारंभ कर दिया जाएगा। जिससे नगर के बाजार वाले क्षेत्र में जल वितरण की व्यवस्था में सुधार हो जाएगा और नलों से प्रेशर से पानी मिलने लगेगा।

8 साल से बंद पड़ी 4 टंकियों में से तीन को किया शुरू

नपा के अनुसार नगर में करीब 8 वर्ष से बनकर तैयार खड़ी 4 पानी की टंकियों में से तीन टंकियों को प्रारंभ किया जा चुका है। अब नगर पालिका कार्यालय परिसर में नवनिर्मित टंकी के साथ ही पूर्व में वार्ड क्रमांक-10 में बनाई हुई पानी की टंकी को एक साथ प्रारंभ किया जाएगा। जिससे करीब आधे नगर में पानी की सप्लाई पूरे प्रेशर के साथ हो पाएगी।

सभी जगह पहुंचाई जा रही पाइप लाइन- नगर में ऐसे चयनित स्थान जहां पर पाइप लाइन नहीं होने के कारण लोगों को अन्य स्त्रोतों या दूर-दराज से पानी की व्यवस्था करना पड़ती है वहां पर पाइप लाइन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बताया गया कि अमृत-2 योजना में नपा द्वारा नगर में 15 किमी की नई पाइप लाइन डालने के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसमें से 12 किमी की पाइप लाइन डालने के लिए स्वीकृति मिली है। इसके चलते 12 किमी की पाइप लाइन डाली जा रही है। बताया गया कि यदि ये पाइप लाइन कम पड़ी तो इसे और बढ़ाया जाएगा।

बार-बार पाइप लाइन फूटने से आई परेशानी- जानकारी के अनुसार नगर में जारी शहरी फोरलेन के निर्माण के कारण कई बार पाइप लाइन फूटने की परेशानी आ चुकी है। ऐसे में नपा का टंकियों को प्रारंभ कर जल वितरण का कार्य प्रभावित हो रहा है। कई बार इस कार्य को पूर्ण करने में परेशानी भी आई है। हालांकि अब नपा के अनुसार एक-डेढ़ माह में दोनों पानी की टंकी को प्रारंभ कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। जिससे नगर में जल संकट की स्थिति नहीं बनेगी।

इनका कहना है- अमृत-2 योजना के तहत नपा कार्यालय परिसर में बनी पानी की टंकी की टेस्टिंग हो चुकी है। इस टंकी के साथ ही पूर्व में वार्ड-10 में बनी पानी की टंकी को प्रारंभ किया जाएगा। इससे नगर में जल वितरण की व्यवस्था सुधर जाएगी। वहीं सभी जगह पाइप लाइन बिछाने का कार्य भी जारी है।

- प्रेम जैन, अध्यक्ष, नगर पालिका-शाजापुर

पेंशनर्स संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। मंगलवार को पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नवीन पेंशन सेल की व्यवस्थाओं में सुधार और 13 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें सेवानिवृत्त हो चुके इन पेंशनर्स को हो रही समस्याओं का उल्लेख करते हुए इनके समाधान की मांग की गई।

अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग एवं संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, मध्यप्रदेश शासन के नाम जिला पंचायत सीईओ प्रभारी एवं एसडीएम मनीषा वास्कले को सौंपे गए ज्ञापन में पेंशनर्स ने बताया कि नवीन पेंशन सेल के गठन के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जबकि प्रशिक्षण के दौरान दावा किया गया था कि सेवानिवृत्ति के सात दिनों के भीतर पीपीओ जारी कर दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में दो से तीन महीने बीतने के बाद भी न तो पीपीओ जारी हो पा रहा है और न ही पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान हो रहा है।

एसोसिएशन का यह भी कहना था कि जिले से भेजे गए सैकड़ों पेंशन प्रकरण भोपाल स्थित पेंशन सेल में लंबित पड़े हैं, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

इसके अलावा जिला पेंशन अधिकारियों के पास भी इन समस्याओं के निराकरण के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। पेंशनर्स ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों के शीघ्र निराकरण, व्यवस्था में सुधार तथा मध्यप्रदेश विद्युत मंडल से सेवानिवृत्त पेंशनरों को पेंशन की गारंटी देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशभर के पेंशनर्स आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

बुरहानपुर पुलिस की अवैध गौवंश तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

थाना शिकापुरा पुलिस द्वारा अवैध गौवंश तस्करी के 11 आरोपीयो को गिरफ्तार कर भेजा जेल, एक फरार

बुरहानपुर/ आयूष भावसार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला बुरहानपुर में बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण मनाये जाने हेतु गौवंश तस्करी को रोकने हेतु वरिष्ठ अधीकारियो व्दारा निर्देशित किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री अशुतोष बागरी, एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शेण्डे के निर्देशन में श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में बकराईद के पूर्व अवैध गौवंश तस्करो के विरूद्ध थाना शिकारपुरा की प्रभावी कार्यवाही की गई थी ।

घटना का विवरणः दिनाँक 11.05.2026 को शिकारपुर पुलिस को मुखबीर सूचना मिली की ग्राम बाडा जैनाबाद के फरदीन पिता हिफाजत, नसीब पिता रसीद तडवी, लाडला पिता प्यारे साहब एवं अपचारी बालक अपने अन्य साथियो के साथ जगंल के रास्ते अवैध गौवंश वध हेतु बुरहानपुर तरफ लेकर जाने वाले है, मुखबीर सूचना पर हमराह फोर्स मुखबीर के बताये स्थान ग्राम बाडा जैनाबाद के कब्रस्तान के पास नाका बंदी कर फरदीन पिता हिफाजत, नसीब पिता रसीद तडवी, लाडला पिता प्यारे साहब, अपचारी बालक व उनके अन्य साथी गौवंश को आपस मे एक दुसरे से रस्सी से बाध कर पिरानी चुभो कर जगल के रास्ते पैदल पैदल क्रूरता पूर्वक मारते पीटते बंध हेतु बुरहानपुर की तरफ ला रहे थे जो पुलिस को देखकर अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गये मौके से 16 नग गौवंश विधिवत जप्तकर जप्तशुदा गौवंश को श्री कृष्ण गौशाला जैनाबाद मे अस्थायी सुपुर्दनामे पर दिया गया, फरार आरोपीयो के विरूद्ध थाना शिकारपुरा पर अपराध क्र. 144/2026 धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रति. अधि. पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।

विवेचना के दौरान बैल हाकने वाले अपचारी बालक एवं आरोपीयो को गिरफ्तार किया गया जिसमें

1.फरदीन पिता हिफाजत
2.नसीब पिता रसीद तड़वी
3लाडला पिता प्यारे साहब
4.अशरफ पिता तुकडू तड़वी
5.शेख जाकिर उर्फ राजू
6.शेख सईद पिता शेख आरिफ
7.आरिश पिता मेहमूद खान
8.शेख वसीम पिता शेख रसीद व्यापारी
9.शेख जुबेर पिता शेख हनीफ
10.शेख एजाज पिता शेख इलियास
11.एक अपचारी बालक

सभी आरोपी ग्राम बड़ा जैनाबाद, बैरी मैदान एवं गुलमोहर मार्केट क्षेत्र के निवासी हैं। न्यायालयीन कार्यवाही में गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल खंडवा भेजा गया।

फरार आरोपी गुडिया पिता बशीर उर्फ शेरा निवासी बैरी मैदान फरार है जिसकी तलाश जारी है।

महत्वपूर्ण भूमिकाः थाना प्रभारी शिकारपुरा संदीप चौरसिया, उप निरीक्षक मनीष पटेल, प्रआर.94 रफीक खाँन, प्रआर. 467 सचिन पटेल, प्रआर. 77 शेख जाकिर, प्रआर. 152 विजय बडकारे, प्रआर. 194 सुनिल पाटीदार, की सराहनीय भूमिका रही है।

दिनदहाड़े उठी आग की लपटें, लाखों का हुआ नुकसान

हादसे में घर की टीवी, कूलर, पंखा और पलंग हुए खाक

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर के सोमेश्वर मार्ग स्थित एक घर में दोपहर में ही अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि जहां यह हादसा हुआ वहां उस समय कोई मौजूद नहीं था जिससे हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन घर में रखा सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया।

घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। आग इतनी तेजी से फैली कि क्षेत्र में धुआं फैल गया, जिससे आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए और अफरा-तफरी मच गई। सामेश्वर मार्ग निवासी अशोक शर्मा के यहां हुए इस हादसे में घर की टीवी, फ्रीज, पंखा, पलंग सहित अन्य सामान इस आगजनी की भेंट चढ़ गया। अशोक शर्मा ने बताया कि वे उस समय घर पर नहीं थे। आग कैसे लगी इस बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है।

धुंआ उठता देखा दौड़े पड़ोसी, बुलाई फायर ब्रिगेड- घर से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास रहने वाले लोगों ने तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और डायल-112 के पायलट कमलेश तथा आरक्षक निलेश मौके पर पहुंचे। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, जब तक आग बुझाई गई तब तक घर का अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो चुका था। प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। पुलिस और संबंधित विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हैं।

लगातार हो रही आगजनी की घटनाएं- भीषण गर्मी का दौर शुरू होते ही नगर सहित जिले भर में आगजनी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। अप्रैल से मई माह में ही नगर में आधा दर्जन से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। तो हाईवे पर भी दो बसों में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। मंगलवार को भी हुई इस घटना में मकान मालिक को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा।

जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। आगामी समय में आने वाले महाराणा प्रताप जयंती, मोहर्रम (ताजिया), गुरू पूर्णिमा, श्रावण मास एवं अन्य त्यौहार शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए आज कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने सभी धर्मावलंबियों से त्यौहारों को मिलजुलकर मनाने के लिए कहा एवं आगामी त्यौहारों की शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने त्यौहारों के दौरान किये जाने वाले आयोजनों के संबंध में सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए कहा। आयोजकगण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में वालेंटियर्स बनाएं और उन्हें पहचान पत्र भी दें। कलेक्टर ने सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिका सीएमओ को निर्देश दिये कि शहर में निजी संस्थाओं एवं मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों, जुलूस मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं एवं कैमरे व्यवस्थित रूप से कार्य करें।

कलेक्टर ने नगरपालिका अधिकारी को जुलूस मार्गों एवं नगर में साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था करने, ट्रॉफिक व स्ट्रीट लाईट चालू करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री को निर्देश दिये कि जुलूस मार्ग की विद्युत लाईनों को पर्याप्त ऊचाईयों पर रखें एवं विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी निर्धारित रूट का निरीक्षण भी करें। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी त्यौहारों के दौरान निर्बाध विद्युत प्रदाय की व्यवस्था रखें।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री घनश्याम मालवीय ने कहा कि आने वाले त्यौहारों को सभी धर्मावलंबी मिलजुलकर मनाएं। उन्होंने कहा कि समय से पूर्व जूलूस आयोजन की अनुमति लें, वालेंटियर्स के नाम पुलिस को उपलब्ध कराएं तथा थाना, वार्ड स्तर पर होने वाली बैठकों में आयोजन की पूरी जानकारी दें। मशाल जुलूस में दी गई अनुमति के अनुसार ही मशालों का उपयोग करने, दो पहियां वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रखने, डीजे का उपयोग नहीं करने आदि के बारे में कहा।

आलोट मे तीन दिवसीय जनकल्याण शिविर का हुआ शुभारंभ

आलोट/ राकेश चौहान/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के मार्गदर्शन में जिले में जनकल्याणकारी योजनाओं/सेवाओं में पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने हेतु शासन के निर्देशानुसार नगरीय निकाय/विकासखंड मुख्यालय पर 3 दिवसीय जनकल्याण शिविरो का आयोजन किया जा रहा है।

आज तहसील आलोट में तीन दिवसीय जनकल्याण शिविर का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया । शिविर में नगर परिषद आलोट से संबंधित 1127 आवेदन 61, नगर पालिका ताल से संबंधित प्राप्त हुए। शिविर में बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने अपनी समस्याओं का निराकरण कराया और शासकीय योजनाओं का लाभ लिया।

शिविर स्थल पर आमजन को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से शासन की योजनाओं एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित करती हुई, प्रदर्शनी भी लगाई गई।

शिविर में विभागों द्वारा योजनाओं/ सेवाओं में पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने हेतु स्टॉल लगाए गए है एवं योजनाओं से संबंधित जानकारी विभागों द्वारा नागरिकों को प्रदान की जा रही है ।

राज्य शासन द्वारा आयोजित जनकल्याण शिविरों में विभिन्न विभागों की 100 से अधिक जनहितैषी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ नागरिकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। शिविरों में अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण, उच्च शिक्षा, उद्यानिकी, ऊर्जा, कृषि, जनजातीय कार्य, नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, परिवहन, पशुपालन, मत्स्य पालन, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, स्वास्थ्य, श्रम, सहकारिता, सामाजिक न्याय तथा सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। शासन का उद्देश्य नागरिकों को उनकी आवश्यक सेवाएं समयबद्ध एवं सरल तरीके से उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके।

शिविरों में जाति, आय, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना/मुख्यमंत्री निकाह योजना, आयुष्मान कार्ड, लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम सूर्य घर योजना, लखपति दीदी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भवन निर्माण अनुज्ञा, नवीन विद्युत एवं नल कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस, आयुष्मान भारत योजना, आवेदक की आयु का चिकित्सा सत्यापन, प्रसूति सहायता का लाभ प्रदान करना, अंकसूची में सुधार, जाति प्रमाण -पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अनेक योजनाओं के आवेदन एवं निराकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

इस फादर्स डे, टाइटन एज और ज़ायलिस की घड़ियों के साथ अपने पिता को दें एक खास उपहार

कुछ उपहार केवल एक अवसर को यादगार बनाते हैं, जबकि कुछ जीवनभर की यादों का हिस्सा बन जाते हैं। इस फादर्स डे, टाइटन की घड़ियों के साथ उस व्यक्ति का सम्मान करें जिसकी ताकत, समझदारी और मौजूदगी ने जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव को आकार दिया है। खोजें टाइटन एज म्यूरल्स की कलात्मक खूबसूरती, ज़ायलिस मारियाना की आधुनिक परिष्कृतता, टाइटन एज फ्यूमाज की बेहतरीन कारीगरी और ज़ायलिस क्रार्ट्ज एनालॉग की शानदार लक्ज़री। हर तरह के पिता को ध्यान में रखकर तैयार की गई ये टाइमपीस केवल उपहार नहीं हैं, बल्कि उनकी यात्रा, उपलब्धियों और जीवनभर की विरासत का उत्सव हैं। क्योंकि कुछ पल केवल एक उपहार से बढ़कर होते हैं–वे एक यादगार विरासत के हकदार होते हैं।

आलोट में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर जानलेवा हमला, स्वास्थ्यकर्मियों ने की बुलडोजर कार्रवाई की मांग

आलोट/ राकेश चौहान/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सिविल अस्पताल आलोट में कार्यरत विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेन्द्र मौर्य पर बीती रात अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, इस हमले में डॉक्टर के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, यह पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, इस घटना से आक्रोशित स्वास्थ्यकर्मि सिविल हॉस्पिटल आलोट से रैली निकालकर थाना परिसर पहुँचे जहाँ नायब तहसीलदार आलोट को अनुविभागीय अधिकारी के नाम पत्र सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है साथ ही संघ ने मांग की है कि आरोपियों पर सख्तकार्यवाहीकी जाए और बचे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, हमलावरों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाए, गिरफ्तारी के बाद आरोपियों का आलोट क्षेत्र में जुलूस निकाला जाए मे, पीड़ित डॉक्टर और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए,मे जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद न हो और भविष्य मे ऐसी स्थिति ना बने, टीआईमुनेन्द्र गौतम ने बताया की अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गयी है और 2 आरोपी राउंडप है बचे आरोपी भी जल्द पुलिस की गिरफ्त मे होंगे और उनपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी! वही विधायक चिंतामणि मालवीय डॉक्टर के घर पहुंचे और उनका हाल जाना और संबंधित आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया और मैं स्वास्थ्य सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा समस्त स्वास्थ्य कर्मचारी मुझ पर विश्वास रखें मैं आपके लिए हमेशा तैयार खड़ा हूं।

मध्यप्रदेश युथ कांग्रेस एवं महिला कांग्रेस के आह्वान पर युथ कांग्रेस आलोट विधानसभा एवं महिला कांग्रेस आलोट द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया

आलोट/ राकेश चौहान/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस एवं महिला कांग्रेस के निर्देशानुसार तथा कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर उठे विवाद के विरोध में आज युवा कांग्रेस आलोट विधानसभा एवं महिला कांग्रेस के नेतृत्व में विशाल विरोध प्रदर्शन पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया है ।

जिसमें कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध पुतला दहन कर चुनाव आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सोपा

साथ ही पुतले को लेकर पुलिस प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर खिचतान हुई साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पुतले को आग के हवाले किया गया।। प्रशासन द्वारा जलते पुतले एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फायर ब्रिगेड द्वारा पानी की बौछार की गई।।

इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अभिनव निगम,रमेश पाठक,राकेश जगदीश पाटीदार,बाबु सिंह गुर्जर,

जनपद पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह परिहार,शहर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पांचाल,युथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रवि सिसोदिया,युथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष शंकर सिंह परिहार भीम,युथ कांग्रेस ताल ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाटीदार,ब्लॉक कांग्रेस मिडिया प्रभारी योगेश निगम, कांग्रेस नेता कालुराम परमार रिछा,आई टी सेल जिला अध्यक्ष कमल डांगी,प्रकाश राड़ोतिया,किसान कांग्रेस अध्यक्ष रुघनाथ सिंह परिहार, मध्यप्रदेश सेवादल प्रदेश सचिव श्रीमती संजू भाटी,नेता प्रतिपक्ष पदमा हिंगड़,कृष्णा बाई,चंदाबाई,द्रौपदी बाई,शांति बाई, काली बाई,सौरम बाई,लक्ष्मी बाई, जिला कांग्रेस सहसचिव ईश्वर सोलंकी,गौरव पामेचा,रणजीत सिंह परिहार,मंगल सिंह देवड़ा,शंकर सिंह चौहान पाटन, अनुपम अरोड़ा,युवराज सिंह परिहार, बालमुकुंद पाटीदार,सहित कई कांग्रेस पदाधिकारियगण,एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। ज्ञापन का वाचन शहर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पांचाल ने किया।।

जनजातीय विकास कार्यक्रम में आने का दिया निमंत्रण, राज्यपाल से मिले सांसद ज्ञानेश्वर पाटील

बुरहानपुर/ आयूष भावसार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मंगलवार को भोपाल स्थित लोक भवन में खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से सौजन्य भेंट की। इस दौरान सांसद ने प्रदेश के विकास, जनकल्याण और जनजातीय समाज के उत्थान से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। भेंट के दौरान सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र के जनजातीय विकासखंड झिरन्या, जिला खरगोन की देवतुल्य जनता की ओर से महामहिम राज्यपाल को आगामी आयोजित होने वाले जनजातीय कल्याण एवं विकास कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति हेतु सादर आमंत्रण भी दिया। सांसद पाटील ने कहा कि महामहिम राज्यपाल जी का स्नेह, जनजातीय समाज के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण और उनके उत्थान के लिए सतत चिंतन समाज के लिए प्रेरणास्रोत है।

उज्जैन तक मिला विस्तार, अब इंदौर नागदा ट्रेन को रतलाम तक बढ़ाने की मांग

सकलेचा, जैन एवं लश्करी ने रेलवे प्रशासन से यात्रियो की सुविधा हेतु करी मांग

नागदा/ राजेश सकलेचा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर- नागदा पैसेंजर ट्रेन क्रमांक 59388 को रतलाम तक विस्तारित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। समाजसेवी राजेश सकलेचा, नितिन जैन (उन्हेल), दिपक जैन एवं गौतम लश्करी ने रेलवे प्रशासन से आग्रह किया है कि वर्तमान में नागदा स्टेशन पर लंबे समय तक खड़ी रहने वाली इस ट्रेन का संचालन रतलाम तक किया जाए, जिससे क्षेत्र के हजारों रेल यात्रियों को सीधा लाभ मिल सके।

उन्होंने बताया कि हाल ही में रेल सेवाओं के विस्तार को लेकर यात्रियों को रतलाम तक ट्रेन बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन विस्तार केवल उज्जैन तक ही सीमित रहा। इससे रतलाम रेलखंड के यात्रियों में निराशा देखी गई। ऐसे में इंदौरङ्कनागदा ट्रेन का रतलाम तक विस्तार एक व्यवहारिक एवं जनहितकारी कदम साबित हो सकता है।

सकलेचा, जैन एवं लश्करी ने बताया कि ट्रेन क्रमांक 59388 इंदौर से चलकर नागदा पहुंचने के बाद लगभग ढाई से तीन घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रहती है। इस अवधि का उपयोग करते हुए ट्रेन को रतलाम तक संचालित किया जा सकता है। इससे इंदौर, उज्जैन, उन्हेल, नागदा, खाचरौद और रतलाम के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच इंदौर, उज्जैन, नागदा, खाचरौद और रतलाम के मध्य रेल सेवाओं के विकल्प सीमित हैं। इसका प्रभाव दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों तथा अन्य रेल उपभोक्ताओं पर पड़ता है। ट्रेन के रतलाम तक विस्तार से इन सभी वर्गों को आवागमन का एक सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। समाजसेवियों का कहना है कि ट्रेन के नागदा स्टेशन पर लंबे समय तक खड़े रहने के बजाय उसका उपयोग रतलाम तक संचालन में किया जाए तो रेलवे संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव होगा। साथ ही इंदौर-उज्जैन- नागदा- रतलाम रेलखंड की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी और क्षेत्रीय यातायात व्यवस्था को नई गति मिलेगी।

राजेश सकलेचा, नितिन जैन (उन्हेल), दिपक जैन एवं गौतम लश्करी ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि इस प्रस्ताव की तकनीकी एवं परिचालन संभावनाओं का अध्ययन कर यात्रियों के हित में सकारात्मक निर्णय लिया जाए। उनका कहना है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही यात्री आवागमन की आवश्यकताओं को देखते हुए ट्रेन क्रमांक 59388 का रतलाम तक विस्तार समय की मांग है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि रेलवे प्रशासन इस प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेता है तो इंदौर, उज्जैन, उन्हेल, नागदा, खाचरौद एवं रतलाम के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा तथा क्षेत्रीय रेल सेवाएं अधिक सुलभ, सुविधाजनक और प्रभावी बन सकेंगी।

पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् विकासखंड रामा-कालीदेवी, जिला झाबुआ के अंतर्गत सेक्टर रामा की ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति, ग्राम राछवा में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिषद् के जिला समन्वयक श्री प्रेम सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण में पौधारोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 तक सभी प्रस्फुटन समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक पौधारोपण करें तथा उसकी जानकारी शासन द्वारा निर्धारित 'माय लाइफ' एप पर अपलोड करें। इस अवसर पर हनुमान मंदिर परिसर में बेलपत्र का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कुओं, तालाबों के गहरीकरण एवं बावड़ियों की साफ-सफाई जैसे जल संरक्षण कार्यों की जानकारी दी गई। साथ ही प्रस्फुटन समिति के कार्यों की समीक्षा करते हुए समिति दस्तावेजों के संधारण, प्रस्फुटन समिति बोर्ड, जन सूचना केंद्र एवं संस्कार केंद्र के नियमित संचालन पर विशेष बल दिया गया। श्री चौहान ने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने समिति सदस्यों से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

बदनावर सेवार्थ सेतु फाउंडेशन द्वारा नगर में जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री किट वितरण कि

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। बदनावर सेवार्थ सेतु फाउंडेशन द्वारा पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत नगर में जरूरतमंद परिवार के बीच पहुंचकर करीब आठ परिवार को राशन सामग्री किट फाउंडेशन की सदस्य आयुषी माथुर द्वारा वितरण किए गए इस अवसर पर पारुल चौहान ने बताया कि सेवार्थ सेतु फाऊंडेशन लगातार जरूरतमंद परिवारों के बीच पहुंचकर उनकी हर प्रकार से सहायता करने हेतु तैयार रहता है एवं उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार हर संभव सहायता करता है फाउंडेशन के सदस्य अपना जन्म दिवस उन परिवारों के बीच में पहुंचकर छोटे-छोटे बच्चों के साथ केक काटकर खुशियां मनाते हैं और उनकी खुशियां देखकर हमें सेवा करने का उत्साह मिलता है।

बदनावर विधानसभा क्षेत्र में 9 नए डॉक्टरों की हुई नियुक्ति

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। विधानसभा क्षेत्र के शासकीय अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 9 नए डॉक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। लंबे समय से चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व विधायक राजवर्धनसिंह दत्तीगांव द्वारा क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजेंद्र शुक्ला से मांग की गई थी। इसी प्रयास के परिणामस्वरूप अब बदनावर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर नए चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। इससे क्षेत्रवासियों को स्थानीय स्तर पर बेहतर एवं समयबद्ध चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

जारी आदेश अनुसार सिविल हॉस्पिटल बदनावर डॉ. विजय नागर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केसूर डॉ. चंचल प्रजापत, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कानवन डॉ. प्रियंका चौहान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काछीबड़ौदा डॉ. भारती हारोड, सिविल हॉस्पिटल कोद डॉ. देवाशीष चौधरी एवं डॉ. प्रचिती प्रकाश जायसवाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुलथान डॉ. कमलेश प्रजापति, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोतरिया - डॉ. कोमल मानसुखानी व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिसगांव में डॉ. अखिलेश कुशवाह की नियुक्ति आदेश जारी हुए है। क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का आभार माना।

बदनावर सिविल अस्पताल में निःशुल्क नेत्र शिविर संपन्न

12 मरीजों में मोतियाबिंद की पुष्टि, 8 ऑपरेशन के लिए मक्सी रवाना

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला अंधत्व निवारण समिति धार, मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल मक्सी एवं लायन्स क्लब बदनावर के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को शासकीय सिविल अस्पताल बदनावर में निःशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के कई जरूरतमंद मरीजों ने पहुंचकर अपनी आंखों का परीक्षण करवाया।

शिविर के दौरान मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल मक्सी से आई विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा कुल 41 नेत्र रोगियों की आंखों की गहन जांच की गई। परीक्षण के पश्चात कुल 12 मरीजों में मोतियाबिंद के लक्षण पाए गए, जिन्हें लेंस प्रत्यारोपण के लिए चिन्हित किया गया। इनमें से 8 गंभीर मरीजों को तुरंत बेहतर उपचार और निःशुल्क ऑपरेशन के लिए विशेष वाहन द्वारा मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल मक्सी भेजा गया।

बदनावर सिविल अस्पताल में निःशुल्क नेत्र शिविर संपन्न- शिविर में आए मरीजों को परामर्श और चिकित्सा सेवाएं देने में मक्सी अस्पताल के नेत्र चिकित्सा सहायक श्री देवेश मिश्रा, सेवानिवृत्त नेत्र चिकित्सा सहायक डॉ. रामगोपाल वर्मा तथा लायन्स क्लब बदनावर के वरिष्ठ सदस्य लायन विष्णु बैरागी ने अपनी महत्वपूर्ण और सराहनीय सेवाएं दीं। उल्लेखनीय है कि बदनावर क्षेत्र के नागरिकों को आंखों के बेहतर इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, इस उद्देश्य से हर माह के तीसरे मंगलवार को सिविल अस्पताल बदनावर में मक्सी अस्पताल का यह नियमित कैंप आयोजित किया जाता है। समिति द्वारा बताय गया की इस श्रृंखला का अगला निःशुल्क शिविर 21 जुलाई 2026 मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। लायन्स क्लब एवं स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस निःशुल्क सेवा का लाभ उठाएं।

विधायक भंवरसिंह शेखावत ने किया विद्युत ट्रांसफार्मर का लोकार्पण

गौशाला के लिए शेड निर्माण की दी मंजूरी

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। क्षेत्रीय विधायक भंवरसिंह शेखावत ने गत दिवस ग्राम पंचमुखी में विधायक निधि से स्थापित नए विद्युत ट्रांसफार्मर का विधिवत लोकार्पण किया। इस विकास कार्य से स्थानीय ग्रामीणों को बिजली की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। लोकार्पण कार्यक्रम के पश्चात विधायक शेखावत ने उमा महेश्वर गौशाला पहुंचकर गोमाता का विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया। इस अवसर पर उन्होंने गौशाला के सुचारू संचालन से जुड़े पदाधिकारियों एवं सदस्यों का सम्मान किया और गौवंश संरक्षण के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की खुले दिल से सराहना की।

सभा को संबोधित करते हुए विधायक श्री भंवरसिंह शेखावत ने कहा गौसेवा एवं गौसंरक्षण हमारी भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। उमा महेश्वर गौशाला न केवल बेसहारा गौवंश की सेवा कर रही है, बल्कि युवाओं को गौपालन, आध्यात्मिक मूल्यों और सामाजिक संस्कारों से जोड़ने का भी सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा कि आज के समय में युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखना और उन्हें सकारात्मक दिशा प्रदान करना बेहद जरूरी है। गौशाला समिति इस दिशा में एक अनुकरणीय और प्रेरणादायी कार्य कर रही है। विधायक निधि को जनता की अमानत बताते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र की आवश्यकताओं और जनभावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा कराया जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष क्षेत्र की दो प्रमुख मांगें रखीं– ग्राम नागदा के समीप चामला नदी पर बैराज (बांध) का निर्माण और उमा महेश्वर गौशाला में एक नए शेड का निर्माण। जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए विधायक शेखावत ने मौके पर ही गौशाला हेतु शेड निर्माण की तुरंत स्वीकृति प्रदान की।

इसके साथ ही चामला नदी पर बैराज निर्माण के प्रस्ताव को लेकर उन्होंने अपने निज सहायक को आगामी आवश्यक शासकीय कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू करने के कड़े निर्देश दिए।

कार्यक्रम में गौशाला समिति के अध्यक्ष भगवानसिंह झाला, उपाध्यक्ष मोहनलाल जायसवाल, सचिव मेहरबानसिंह झाला, कोषाध्यक्ष रामचरनदास वैष्णव, आशीष भाकर (बिलोदा), नितिन सांखला, कमलसिंह सिसोदिया, राजेश राठौड़, विनोद गेहलोत, गोविंदसिंह, लाखन पटेल, ओमप्रकाश पाटीदार और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। उक्त संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी विधायक के निज सहायक आर.पी. सिंह द्वारा प्रदान की गई है।

मालवा में भगवान विश्वकर्मा का भव्य मंदिर बनाया जाएगा, मंदिर निर्माण के लिए समिति का गठन, सनोलिया बने अध्यक्ष

नागदा/ राजेश सकलेचा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जूना गुजराती सुतार विश्वकर्मा समाज के गांव पलवा (तहसील बड़नगर) स्थित लगभग 150 वर्ष प्राचीन भगवान विश्वकर्मा मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मंदिर निर्माण एवं संरक्षण के लिए गांव पलवा में समाज की केंद्रीय समिति उज्जैन के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांतिलाल विश्वकर्मा (कनासिया, शाजापुर) ने की, जबकि केंद्रीय समिति के अध्यक्ष अशोक शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

बैठक में मंदिर जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य को गति देने के लिए नई समिति का गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष पद पर कैलाश सनोलिया (नागदा) को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। बैठक से लौटने के बाद श्री सनोलिया ने बताया कि मालवा जूना गुजराती सुतार समाज का यह मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना है और अपनी अद्भुत लकड़ी की कलाकारी के लिए जाना जाता है। वर्तमान में यह प्राचीन धरोहर जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है और इसके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है।

बैठक में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, झाबुआ, शाजापुर एवं आगर जिलों से आए लगभग 150 प्रमुख समाजजनों ने भाग लिया। प्रस्तावित मंदिर का निर्माण लगभग 1600 वर्गफीट क्षेत्र में किया जाएगा, जिस पर करीब 35 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक राशि समाजजनों के सहयोग एवं जनसहभागिता से जुटाई जाएगी।

समिति के पदाधिकारी- समिति के उपाध्यक्ष के रूप में राकेश पटेल जलोदिया (धार), संजय शर्मा मौलाना (बड़नगर), सुरेश शर्मा (बड़नगर), डॉ. श्रीराम शर्मा दसाई (धार) तथा प्रशांत शर्मा (उज्जैन) को मनोनीत किया गया। किशोर शर्मा (बड़नगर) को कोषाध्यक्ष बनाया गया।

संरक्षक मंडल में अशोक शर्मा (उज्जैन), रामचंद्र सुनेरिया (उज्जैन), रमेश कश्यप (देवास) एवं दिनेश विश्वकर्मा (लोहाना, बड़नगर) को शामिल किया गया। बैठक में राजेंद्र कारपेंटर (शाजापुर), दुर्गाप्रसाद विश्वकर्मा (इंदौर), राजेंद्र शर्मा इंजीनियर (देवास), ओमप्रकाश कारपेंटर (शाजापुर), प्रमोद कारपेंटर (देवास), शिवनारायण विश्वकर्मा (हाटपिपल्या), भाजपा उज्जैन शहर अध्यक्ष विशाल शर्मा, राहुल सिसौदिया (इंदौर), सिद्धनाथ कारपेंटर (इंदौर), संजय शर्मा (उज्जैन), अरुण मकवाना (उज्जैन), दिनेश सनोलिया (खरसौद कला) एवं संतोष शर्मा (उज्जैन) सहित अनेक समाजजनों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन जगदीश कारपेंटर (उज्जैन) ने किया।

ईद की दावत बनी मौत का जाल! भतीजे ने पत्नी संग मिलकर काका को उतारा मौत के घाट, 'दृश्यम' स्टाइल में रची साजिश का खुलासा

बड़नगर/ महेश सोनगरा/ दैनिक मालावा हेराल्ड। बड़नगर पुलिस ने ग्राम पीरझलार विगत दिनों हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात से पर्दा उठा दिया है। गुमशुदा सुल्तान पटेल की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका सगा भतीजा ही निकला, जिसने अपनी पत्नी और एक नाबालिग के साथ मिलकर दृश्यम फिल्म की तर्ज पर पूरी साजिश रची थी।

करीब दो हफ्ते तक रहस्य बने इस मामले को उज्जैन पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सुलझाते हुए आरोपी भतीजे नौशाद और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।

गुमशुदगी से शुरू हुआ हत्या का खेल- 28 मई 2026, ईद के दिन सुल्तान पटेल अचानक लापता हो गया। परिवार की सूचना पर बड़नगर थाने में गुम इंसान दर्ज कर पुलिस ने तलाश शुरू की। लेकिन मामला तब चौंकाने वाला मोड़ ले गया जब 6 जून को यशवंत सागर तालाब के पास झाड़ियों में एक बोरे में बंद सड़ी-गली लाश मिली।

परिजनों ने कपड़ों और टूटे दांत के आधार पर पहचान की–यह लाश सुल्तान पटेल की ही थी।

चरित्र शंका ने करवा दी खून की साजिश- जांच में सामने आया कि मृतक का भतीजा नौशाद अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर काका सुल्तान पर शक करता था। इसी शक ने उसे हैवान बना दिया।

ईद के दिन नौशाद ने सुल्तान को घर पर खाने के बहाने बुलाया। घर के अंदर पहले विवाद हुआ और फिर गुस्से में नौशाद ने मोगरी से हमला कर दिया। इसके बाद टॉवेल से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई।

आधी रात को 'सबूत मिटाने' की साजिश- हत्या के बाद आरोपी ने लाश को बोरे में भरकर अपनी स्विफ्ट कार में रखा और आधी रात को चांदनखेड़ी के आगे यशवंत सागर डेम की झाड़ियों में फेंक दिया।

इतना ही नहीं, रिश्तेदारों को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी भी गढ़ी गई कि सुल्तान का किसी और से झगड़ा हुआ था।

पुलिस की सूझबूझ से खुला राज- पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देशन में बनी टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और लगातार पूछताछ के आधार पर सच्चाई तक पहुंच बनाई। आखिरकार 15 जून को आरोपी नौशाद और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल मोगरी, अन्य सामान और स्विफ्ट कार जब्त कर ली गई।

नाबालिग भी शामिल, भेजा गया बाल गृह- इस सनसनीखेज वारदात में एक नाबालिग की भी भूमिका सामने आई, जिसे बाल संरक्षण में लिया गया है। वहीं महिला आरोपी को भैरवगढ़ जेल भेजा गया है।

सराहनीय भूमिका- उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंघार, उनि. विकास सिंह देवडा, उनि. सुरेन्द्र सिंह गरवाल, उनि. चाँदनी पाटीदार, सउनि नारायण वास्केल, सउनि. सरदारसिंह भगोरा, प्रआर. रामनारायण, प्रदीप डामोर, राहुल राठोर, हेमराज खरे, आरक्षक महेश मोर्य, अजय, मनोहर मोहरी, स्वरूप हिरवे, नारायण सारा, कैलाश गरवाल, महिला आरक्षक सीमा सिंगार, ज्योति हाडा, अनिता डामोर की सराहनीय भूमिका रही।

पाडलवा जनकल्याण शिविर का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने मंगलवार को जनपद पंचायत राणापुर के क्लस्टर पाडलवा में आयोजित जनकल्याण शिविर का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं एवं योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों एवं हितग्राहियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जनकल्याण शिविरों के माध्यम से शासन के 23 विभागों की 110 से अधिक सेवाएं एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक से अधिक संख्या में शिविर का लाभ लेने और अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों से चर्चा कर उर्वरक वितरण व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने किसानों को ई-विकास प्रणाली के माध्यम से ई-टोकन जनरेट कर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार खाद प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने बताया कि भूमि के रकबे के अनुसार एक बार उर्वरक प्राप्त करने के पश्चात आवश्यकता होने पर पुनः ई-टोकन लेकर खाद प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिले में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है तथा किसी भी किसान को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। कलेक्टर ने शिविर में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए एक आवेदक द्वारा फौती नामांतरण एवं नाम जोड़ने संबंधी आवेदन पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। संबंधित प्रकरण का निराकरण कर आवेदक को संशोधित अभिलेखों की प्रति उपलब्ध कराई गई।

कलेक्टर ने राणापुर में सचिवों एवं पटवारियों की बैठक लेकर दिए निर्देश

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने राणापुर में सचिवों एवं पटवारियों की बैठक लेकर जनकल्याण शिविरों की प्रगति एवं शासन की प्राथमिकताओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनकल्याण शिविर शासन की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उनके निकट उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी अधिकारी-कर्मचारी शिविरों में प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से निराकरण करें तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं के लाभ से वंचित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि सचिव , पटवारी एवं कोटवार जनकल्याण शिविरों की जानकारी दें तथा अधिक से अधिक लोगों को शिविरों में पहुंचकर लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। पटवारी श्री गोपाल जोशी द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में अच्छा कार्य करने पर सराहना की। बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने फार्मर आईडी का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने, नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा भूमि संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

पानी का टैंकर चुराने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे! 8 लाख का माल बरामद, ट्रैक्टर समेत गिरोह गिरफ्तार

बड़नगर/ महेश सोनगरा/ दैनिक मालावा हेराल्ड। संपत्ति संबंधी अपराधों पर लगाम कसते हुए भाटपचलाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पानी का टैंकर चोरी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गया टैंकर और घटना में इस्तेमाल ट्रैक्टर जब्त किया है। बरामद माल की कुल कीमत करीब 8 लाख रुपये बताई जा रही है।

पंचायत का टैंकर बना चोरों का निशाना- घटना 14 जून 2026 की है, जब ग्राम पंचायत सिलोदिया के पंचायत सचिव चित्रागंद शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मुंगावदी गांव के सामुदायिक भवन के पास खड़ा शासकीय पानी का टैंकर अज्ञात बदमाश चुराकर ले गए। सूचना मिलते ही भाटपचलाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।

दो दिन में खुला चोरी का राज- पुलिस टीम ने तेजी दिखाते हुए महज दो दिन में ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया। 16 जून को पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोच लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में–बबलु गुर्जर (26),सुरेश सिंह गुर्जर (46),ईश्वर सिंह गुर्जर (25) शामिल हैं।

ट्रैक्टर से खींचकर ले गए टैंक- जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सुनसान जगह का फायदा उठाकर टैंकर को ट्रैक्टर से जोड़कर चोरी किया और फरार हो गए।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से– पानी का टैंकर (कीमत 2 लाख) पॉवर ट्रेक कंपनी का ट्रैक्टर (कीमत 6 लाख)बरामद कर लिया।

आरोपी हैं पुराने अपराधी- पुलिस के अनुसार आरोपी सुरेश सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। उसके खिलाफ पहले से ही नागदा थाने में अपराध दर्ज है, जिससे साफ है कि यह गिरोह पहले भी वारदातों में शामिल रहा है।

पुलिस की सख्ती से टूटे हौसले- पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करणदीप सिंह और एसडीओपी आकांक्षा बेछोटे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सतेन्द्र सिंह चौधरी और उनकी टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा किया।

टीम की सराहनीय भूमिका- इस कार्रवाई में पुलिस टीम के कई अधिकारियों और जवानों ने अहम भूमिका निभाई, जिनकी सराहना की जा रही है।

कलेक्टर ने ढोल्यावड एवं पारा के जनकल्याण शिविरों का किया निरीक्षण

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने जनपद पंचायत राणापुर के क्लस्टर ढोल्यावड तथा जनपद पंचायत रामा के क्लस्टर पारा में आयोजित जनकल्याण शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शिविरों में प्राप्त आवेदनों, हितलाभ वितरण तथा विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी ली।

कलेक्टर ने उपस्थित ग्रामीणों एवं आवेदकों को संबोधित करते हुए कहा कि जनकल्याण शिविरों के माध्यम से शासन के 23 विभागों की 110 सेवाओं एवं जनहितकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने तथा पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया।

उन्होंने ग्रामीणों को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में अपने सुझाव देने के लिए प्रेरित किया तथा बताया कि नागरिकों के सुझाव नीति निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही किसानों को उर्वरक वितरण की ई-विकास प्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि खाद प्राप्त करने के लिए ई-टोकन की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे किसानों को सुविधा होगी तथा वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं एवं सुझाव सुने तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

विकसित भारत के संकल्प का मंथन 18 जुन 2026 को

बुरहानपुर में 12 साल विश्वास,विकास और जनकल्याण विषय पर प्रबुद्धजन संगोष्ठी

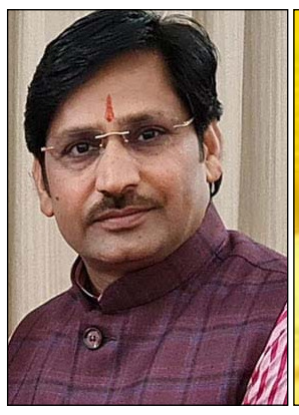

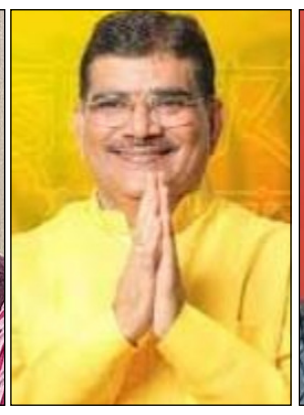

बुरहानपुर/ आयूष भावसार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी जिला बुरहानपुर द्वारा दिनांक 18 जून 2026 गुरुवार को समय सायं 5.30 बजे राजस्थान भवन, इंदिरा कॉलोनी, बुरहानपुर मे प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया है।

उपरोक्त जानकारी भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज माने एवं जिला महामंत्री सर्वश्री जिला महामंत्री सर्वश्री चिंतामण महाजन,संजय जाधव,ईश्वर चौहान ने देते हुवे बताया कि प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करने हेतु म.प्र. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एंव पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री सुमेरसिह सोलंकी मुख्य वक्तृता के रूप में पधार रहे है।

यह प्रबुद्धजन सम्मेलन सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटील, प्रदेश भाजपा प्रवक्तृता,पूर्व केबिनेट मंत्री,विधायक बुरहानपुर विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस दीदी,नेपानगर विधायक सुश्री मंजु राजेन्द्र दादु, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गंगाराम मार्को , उपाध्यक्ष श्री गजानन महाजन, महापौर श्रीमती माधुरी अतुल पटेल, शाहपुर नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती साधना विरेन्द्र तिवारी, बुरहानपुर जनपद अध्यक्ष श्रीमती सोनाली प्रदीप पाटील, उपाध्यक्ष श्रीमती आशा विनोद पाटील, खकनार जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती आरती निलेश चौकसे ,शाहपुर नगर परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती रजनी गोपाल चौधरी, सहित जनप्रतिनिधी एवं संगठन पदाधिकारी ,कार्यकर्तागण की गरीमामयी उपस्थिती में सम्पन्न होगा।

आयोजन जिला टोली संयोजक श्री बलराज नावानी एवं सदस्य श्री प्रदीप पाटिल, श्री सुनील वाघे, श्रीमती प्रियंका सातारकर, श्रीमती सुधा चौकसे, श्रीमती आरती चौकसे भारतीय जनता पार्टी जिला बुरहानपुर ने जिले के समस्त सामाजीक संगठनो के पदाधिकारी,प्राध्यापक,डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, व्यापारी, उद्योगपति, कृषक,विभिन्न समाजो के अध्यक्ष,एसोसिएशन पदाधिकारीयों को सादर आमंत्रित करते हुवे समस्त अपेक्षित गणमान्य जनो से आग्रह है कि कार्यक्रम मे शामिल हो कर आयोजन को सफल बनाए।

स्वाध्याय भवन चौड़ीकरण व दोराया कॉलोनी की समस्याओं पर शिवसेना का हल्लाबोल

बड़नगर/ महेश सोनगरा/ दैनिक मालावा हेराल्ड। साध्य भवन रोड चौड़ीकरण की लंबित मांग, वार्ड क्रमांक 18 दोराया कॉलोनी की बदहाली और शहर की विभिन्न प्रमुख जनसमस्याओं को लेकर आज शिवसेना ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका परिसर पहुंचकर नपा अध्यक्ष और मुख्य नगरपालिका अधिकारी का घेराव किया और तीखा आक्रोश व्यक्त किया। शिवसैनिकों ने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रशासन केवल आश्वासन की राजनीति बंद करे, अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा, धरातल पर काम दिखना चाहिए।

?इस दौरान शिवसेना प्रमुख प्रभात पुरानिया एवं शिवसेना नगर अध्यक्ष संतोष बगेरवाल ने संयुक्त रूप से नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि साध्य भवन रोड चौड़ीकरण का काम लंबे समय से अटका हुआ है, जिससे आए दिन जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इसके साथ ही नेताओं ने वार्ड क्रमांक 18 (दोराया कॉलोनी) की गंभीर मूलभूत समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों की मौजूदगी में स्थानीय व्यवस्थाओं का सघन निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव और गंदगी के ढेर देखकर नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए।

शिवसेना प्रमुख व नगर अध्यक्ष ने मांग की है कि आगामी मानसून (बारिश) के मद्देनजर नगर के सभी छोटे-बड़े नालों की सफाई समय से पहले युद्धस्तर पर पूरी की जाए। विशेषकर जो नाले गंदगी और मलबे के कारण पूरी तरह जाम हैं, उन्हें तुरंत साफ कराया जाए ताकि दोराया कॉलोनी और पूरे बड़नगर में जलभराव व गंदगी की स्थिति निर्मित न हो।

घेराव और प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से शिवसेना प्रमुख प्रभात पुरानिया एवं नगर अध्यक्ष संतोष बगेरवाल के साथ जिला महासचिव राजेश कायस्थ, तहसील अध्यक्ष दिनेश सुजेरा, तहसील महामंत्री लवेश पोरवाल, युवा नगर अध्यक्ष आयुष चौरसिया सहित बड़ी संख्या में शिवसैनिक, महिला सेना की पदाधिकारी और दोराया कॉलोनी के त्रस्त रहवासी उपस्थित रहे।

सुसनेर में प्रशासनिक फेरबदल, कई विभागों में नए अधिकारियों की पदस्थापना

प्रशासनिक सर्जरी के तहत सुसनेर में अधिकारियों के तबादले

सुसनेर/ गिरिराज बंजारिया/ दैनिक मालवा हेराल्ड। राज्य शासन द्वारा जारी प्रशासनिक स्थानांतरण आदेशों के तहत सुसनेर क्षेत्र में विभिन्न विभागों के अधिकारियों का फेरबदल किया गया है। इस प्रशासनिक सर्जरी के बाद कई महत्वपूर्ण विभागों में नए अधिकारियों की पदस्थापना की गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को अन्य जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासनिक बदलावों के चलते क्षेत्र के शासकीय कार्यालयों में हलचल का माहौल बना हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सुसनेर की अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) किरण वरखड़े का स्थानांतरण सीहोर जिले में किया गया है। उनके स्थान पर नए एसडीएम की पदस्थापना का आदेश फिलहाल जारी होना शेष है। एसडीएम के तबादले के बाद राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा बनी हुई है।

वहीं जेल विभाग में भी बदलाव किया गया है। देपालपुर में पदस्थ सहायक जेल अधीक्षक रामसहाय कुशवाह का स्थानांतरण सुसनेर किया गया है। उनके आगमन से स्थानीय जेल प्रशासन को नया नेतृत्व मिलेगा।

नगर परिषद सुसनेर में भी प्रशासनिक परिवर्तन हुआ है। छापीहेड़ा में पदस्थ प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरीओम शर्मा को सुसनेर का प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाया गया है। जबकि वर्तमान में सुसनेर में पदस्थ ओ.पी. नागर का स्थानांतरण रायसेन कर दिया गया है। नगर परिषद में हुए इस बदलाव से नगरीय विकास एवं विभिन्न निर्माण कार्यों की गति पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जनपद पंचायत सुसनेर में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र सिंह धाकरे का स्थानांतरण बुधनी (जिला सीहोर) किया गया है। उनके स्थान पर किस अधिकारी की नियुक्ति होगी, इसका आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। जनपद पंचायत से जुड़े विकास कार्यों, ग्रामीण योजनाओं एवं पंचायतों के प्रशासनिक संचालन को देखते हुए नए सीईओ की नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है।

लगातार हुए इन स्थानांतरणों से सुसनेर के प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। राजस्व, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं जेल विभाग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए अधिकारियों की तैनाती से कार्यप्रणाली में भी बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल एसडीएम एवं जनपद पंचायत सीईओ के नए पदस्थापना आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है, जिसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगी।

कलेक्टर ने राणापुर ट्रेंचिंग ग्राउंड एवं सब्जी मंडी का किया निरीक्षण

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जनसुनवाई में शामिल होने से पूर्व कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने राणापुर नगर क्षेत्र में ट्रेंचिंग ग्राउंड एवं सब्जी मंडी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ट्रेंचिंग ग्राउंड के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्रोत स्तर पर कचरे के पृथक्करण (सोर्स सेग्रीगेशन) की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने कहा कि ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए, जिससे स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने ट्रेंचिंग ग्राउंड परिसर में पौधारोपण करने तथा परिसर को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने नगर क्षेत्र में साफ-सफाई एवं पेयजल व्यवस्था की भी जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि नागरिकों को स्वच्छ वातावरण एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

नवागत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शेण्डे ने संभाला पदभार, कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर शाखा प्रभारीयो की ली बैठक

बुरहानपुर/ आयूष भावसार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नवागत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शेण्डे ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर पुलिसिंग एवं जनसेवा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

निरीक्षण के दौरान श्रीमान ने कार्यालय में संचालित विभिन्न शाखाओं के अभिलेखों, कार्यप्रणाली, तथा कार्यालयीन व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने शाखा प्रभारियों से शाखा के कार्यों, की जानकारी प्राप्त करते हुए कार्यों के प्रभावी एवं समयबद्ध निष्पादन पर विशेष जोर दिया। इसके उपरांत उन्होंने सभी शाखा प्रभारियों एवं कर्मचारियों की बैठक आयोजित कर विभागीय कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग का मूल उद्देश्य आमजन को त्वरित, संवेदनशील एवं प्रभावी सेवाएं प्रदान करना है, जिसके लिए प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।

बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश- कार्यालयीन कार्यों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

लंबित प्रकरणों एवं पत्राचार का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए।

अभिलेखों एवं दस्तावेजों का सुव्यवस्थित संधारण एवं अद्यतन रिकॉर्ड रखा जाए।

शासन एवं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों का समय पर पालन सुनिश्चित किया जाए।

आमजन से जुड़े प्रकरणों में संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाए।

शाखाओं के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्यों की गति एवं गुणवत्ता बढ़ाई जाए।

तकनीक आधारित कार्यप्रणाली को बढ़ावा देकर कार्यालयीन दक्षता में वृद्धि की जाए।

अनुशासन, जवाबदेही एवं पारदर्शिता को विभागीय कार्यसंस्कृति का अभिन्न अंग बनाया जाए।

श्रीमान द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जिला पुलिस की कार्यक्षमता एवं जनता के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण तथा नागरिकों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए पुलिस विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा।

निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित शाखा प्रभारी एवं कार्यालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे।

मालिक, प्रकाशक, मुद्रक विजय शर्मा द्वारा 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं भगवती ऑफसेट 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक - विजय शर्मा, मो.नं. 94250-22499, फोन 0734-2553435 प्रधान संपादक : शुभम ताम्रकार (सभी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)

महामंडलेश्वर सुमनानंद को जान से मारने की धमकी, पत्र में लिखा- अब तेरी बारी, जहन्नुम में जाएगा तू

धमकी भरे पत्र में उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड और दिल्ली की घटना का जिक्र- पुलिस जांच में जुटी

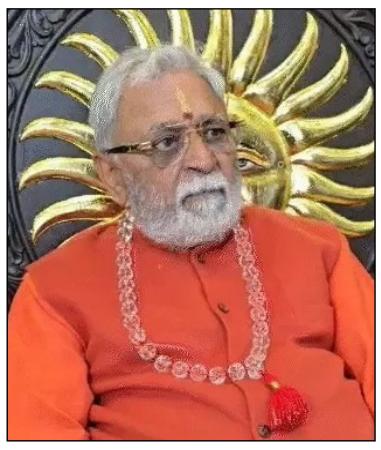

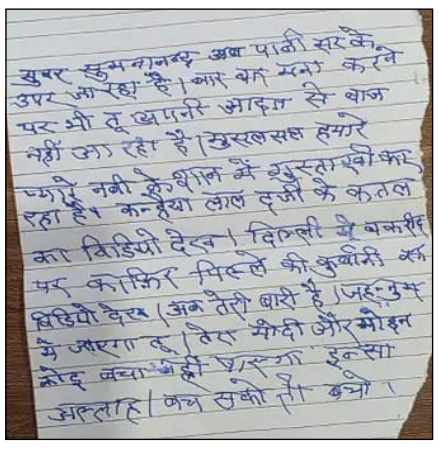

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। मंगलनाथ रोड स्थित गंगाघाट श्री मौन तीर्थ पीठ के पीठाधीश्वर एवं निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर डॉ. सुमनानंद गिरि महाराज को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी एक हस्तलिखित पत्र के जरिए दी गई है, जिसमें न केवल उन्हें मौत के घाट उतारने की चेतावनी दी गई है, बल्कि उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड जैसा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। पत्र में धार्मिक भावनाओं से जुड़े विवादित आरोप लगाते हुए बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया है।

जानकारी के अनुसार गंगाघाट स्थित मौन तीर्थ पीठ पर सोमवार शाम यह पत्र पहुंचा था। मंगलवार को लिफाफा खोलने पर उसमें हाथ से लिखा धमकी भरा संदेश मिला। पत्र उत्तर प्रदेश के महू क्षेत्र से भेजा गया बताया जा रहा है। पत्र में लिखा गया है कि अब तेरी बारी है, जहन्नुम में जाएगा तू। तेरा मोदी और मोहन कोई नहीं बचा पाएगा। साथ ही उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल और दिल्ली में हाल ही में हुई हत्या का जिक्र करते हुए भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई है।

धमकी मिलने के बाद महामंडलेश्वर डॉ. सुमनानंद गिरि ने तत्काल पुलिस अधीक्षक को इसकी जानकारी दी और सुरक्षा की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और धार्मिक जागरण से जुड़े कार्यों के कारण उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि पूर्व में भी कई बार धमकियां मिलने और हमले होने के बावजूद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई।

तीसरी बार मिला धमकी भरा पत्र - महामंडलेश्वर के अनुसार यह पहला अवसर नहीं है जब उन्हें इस प्रकार की धमकी मिली हो। वर्ष 2023 में अखाड़ा परिषद की बैठक के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उर्दू में पत्र भेजकर धमकी दी थी। इसके बाद वर्ष 2025 में प्रयागराज से भेजे गए एक पत्र में भी उनका ÷सिर तन से जुदा÷ करने की धमकी दी गई थी। अब वर्ष 2026 में फिर एक नया पत्र सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

धर्मांतरण और विवाह आयोजनों के कारण रहे चर्चा में- महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरि का मौन तीर्थ आश्रम पिछले कुछ वर्षों से धार्मिक दीक्षा, धर्म परिवर्तन और अंतरधार्मिक विवाहों के कारण लगातार सुर्खियों में रहा है। आश्रम में कई मुस्लिम युवक-युवतियों द्वारा स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाने के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 23 जून 2024 को उज्जैन निवासी अनिकेत चौबे और तलाकशुदा मुस्लिम महिला फरहा का विवाह भी इसी आश्रम में वैदिक रीति-रिवाज से कराया गया था। फरहा और उनकी बेटी ने भी सनातन धर्म स्वीकार किया था। इसके अलावा 31 मई 2026 को गांधी नगर निवासी सलमान खान ने आश्रम में धार्मिक अनुष्ठान के बाद सनातन धर्म अपनाया था और उनका नया नाम शांतनु रखा गया था।

पुलिस जांच शुरू- धमकी भरा पत्र सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पत्र किसने भेजा, उसका उद्देश्य क्या था और उसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी पड़ताल की जा रही है। वहीं धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लगातार तीसरी बार मिली धमकी ने महामंडलेश्वर की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

नई शिक्षा नीति और एआई के दौर में शिक्षकों को बनना होगा टेक-सैवी

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और तकनीक के इस तेजी से बदलते दौर में शिक्षकों को निरंतर अपडेट रहना होगा। आज का विद्यार्थी तकनीक से भली-भांति परिचित है, इसलिए शिक्षक का टेक-सैवी होना भी आवश्यक है। पहले उत्कृष्ट शिक्षक की पहचान चाक एंड टॉक पद्धति से होती थी, लेकिन आज स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल संसाधन और एआई जैसे साधनों का प्रभाव बढ़ गया है।

यह बात विद्या भारती शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के देवकीनंदन चौरसिया ने कही। वे लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति द्वारा आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग के पांचवें दिन 21वीं सदी के शिक्षक की भूमिका और चुनौतियां विषय पर बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता के विकास पर बल देती है। शिक्षक अब केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, मेंटर और फेसिलिटेटर है। विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए शिक्षक को विषय और समसामयिक ज्ञान बढ़ाना होगा। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा और मूल्य शिक्षा को शिक्षण का अभिन्न अंग बनाना होगा। विद्यार्थियों में बढ़ते तनाव को देखते हुए वर्तमान में शिक्षक का एक अच्छा काउंसलर होना भी जरूरी है।

शिक्षकों ने दी एआई और पर्यावरण संरक्षण पर प्रस्तुति- प्रशिक्षण वर्ग के प्रथम सत्र में शिक्षकों ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी प्रस्तुति दी। सत्र का संचालन अंजलि मोदी ने किया। इसमें दिव्या शुक्ला ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में शिक्षक की भूमिका पर बात की। प्रमोद जानी ने समाज सेवा, स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के महत्व को समझाया। सुधीर सोलंकी ने एआई सेक्टर के उभरते ट्रेंड्स और इसके नैतिक उपयोग पर विचार साझा किए। वहीं, डॉ. अंजलि शाह ने शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की भावना विकसित करने पर जोर दिया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ समापन- इससे पूर्व द्वितीय सत्र का शुभारंभ संगठन मंत्र एवं मां सरस्वती के समक्ष पुष्पांजलि के साथ हुआ। इसका संचालन आभा शर्मा ने किया। मंच पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी गिरीश भालेराव एवं लोकमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शैलेष त्रिपाठी उपस्थित रहे। तृतीय सत्र पूरी तरह मनोरंजन पर केंद्रित रहा, जिसमें शिक्षण समिति की विभिन्न इकाइयों के शिक्षकों ने भजन, गीत व नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी संयोजक डॉ. शैलेष त्रिपाठी ने दी।

एडीएम द्वारा विभिन्न मामलों में जनसुनवाई की गई

उज्जैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। एडीएम श्री अत्येन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा मंगलवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में विभिन्न मामलों में जनसुनवाई की गई। घट्टिया तहसील के ग्राम निपानिया सुनार के रहवासियों ने आवेदन दिया कि गांव स्थित मंदिर में पुजारी के छोटे भाई द्वारा दस्तावेजों में हेराफेरी कर स्वयं की नियुक्ति करवा ली गई है। इस पर एडीएम ने एसडीएम घट्टिया को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बड़नगर तहसील के ग्राम माधवपुरा निवासी बंसीलाल ने आवेदन दिया कि उनकी स्वामित्व की कृषि भूमि पर गांव के एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इस पर तहसीलदार बड़नगर को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। घट्टिया तहसील के ग्राम उज्जैनिया निवासी जसपाल सिंह ने आवेदन दिया कि गांव में खेत की ओर जाने वाले शासकीय मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। इसके कारण स्थानीय लोगों को कृषि कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर एसडीएम घट्टिया को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार अपर कलेक्टर श्री शाश्वत शर्मा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा अन्य मामलों में भी जनसुनवाई की गई।

प्राणघातक हमले में शामिल 3 नाबालिग हिरासत में

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। गाड़ी टकराने पर हुए विवाद में 3 छात्रों पर प्राणघातक हमला करने में शामिल 3 नाबालिगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तीनों को मंगलवार को बाल न्यायालय में पेश किया गया।

इंदिरानगर में 12 जून को स्वीफ्ट डिजायर कार और 2 थार गाड़ी से आये कुछ युवकों द्वारा गाड़ी टकराने के विवाद में तीन छात्र गोलू उर्फ जय धन्नानी अवंतिपुरा और दोस्त कार्तिक यादव, प्रणय यादव पर चाकू, हॉकी, लोहे की रॉड और हथियारों से हमला कर दिया था। मामले में चिमनगंज थाना पुलिस ने गोलू उर्फ जय की शिकायत पर मामले में प्रकरण दर्ज किया था। 2 दिनों की तलाश के बाद हमले में शामिल 3 नाबालिगों को सोमवार देर शाम हिरासत में ले लिया गया। जिनसे पूछताछ कर उनके साथियों की जानकारी जुटाई जा रही है। तीनों को बाल न्यायालय में पेश किया गया। विदित हो कि तीनों घायल छात्र दशहरा मैदान चाय काफी कैफे पर खड़े थे, उसी दौरान स्वीफ्ट डिजायर कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी। तीनों छात्रों ने कार चालक का विरोध करने का प्रयास किया तो चालक ने उन पर कार चढ़ाने का प्रयास किया था और भाग निकला था। जिसके बाद मामला इंदिरानगर चौराहा तक पहुंचा तो जहां कार चालक ने अपने साथियों को बुलाकर तीनों पर हमला कर दिया था।

हत्या का आरोपी भाई गिरफ्तार- हीरामिल की चाल में शुक्रवार-शनिवार रात मां से विवाद करने पर मनीष टटवाल की चाकू मारकर छोटे भाई सागर उर्फ नाना ने हत्या कर दी थी। देवासगेट थाना पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर सागर की तलाश शुरू की थी। सोमवार रात उसके हीरामिल की चाल क्षेत्र में आने का सुराग मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की और उसके ठिकानों पर दबिश मारना शुरू किया। देर रात पुलिस ने आरोपी सागर को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार सुबह पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर झाड़ियां में छुपा कर रखा गया चाकू बरामद किया गया। दोपहर में न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया है।

ऑपरेशन नीलगाय फ्लॉप... लाखों खर्च किए, लेकिन हाथ लगी सिर्फ चार नीलगाय

हांका पद्धति पर दांव पड़ा भारी - फसल बचाने की योजना अगले साल तक टली - अब ग्रामीणों के प्लान पर करेगा काम वन विभाग

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। फसलों को नुकसान पहुंचा रही नीलगायों से किसानों को राहत दिलाने के लिए वन विभाग ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया, लेकिन नतीजे उम्मीद के विपरीत रहे। करीब 400 नीलगायों को पकडऩे के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया अभियान आखिरकार सिर्फ चार नीलगायों तक सिमट गया। अब अभियान की असफलता के बाद वन विभाग ने पूरा सामान समेट लिया है और अगले वर्ष नई रणनीति के साथ फिर से मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है।

उज्जैन जिले के राघौपिपलिया और ब्रजराजखेड़ी क्षेत्र में लंबे समय से नीलगायों का आतंक किसानों की चिंता बना हुआ है। खेतों में खड़ी फसलों को लगातार नुकसान पहुंचने से ग्रामीण कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके बाद वन विभाग ने अफ्रीकन बोमा तकनीक के जरिए नीलगायों को पकडऩे की योजना बनाई थी, लेकिन खर्च और विभागीय औपचारिकताओं से बचने के लिए हेलीकॉप्टर की जगह हांका पद्धति अपनाई गई। यही फैसला अभियान की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ।

अभियान में 150 से ज्यादा ग्रामीणों को शामिल किया गया और उन्होंने अपने स्तर पर भी सहयोग किया, लेकिन नीलगायों को नियंत्रित करने की पूरी कवायद अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी। ग्रामीणों का कहना है कि सही समय पर अभियान नहीं चलाया गया और हेलीकॉप्टर जैसी आवश्यक व्यवस्था भी नहीं थी, जिससे नीलगायों को बोमा तक पहुंचाने की योजना विफल हो गई। अब वन विभाग ने अगले वर्ष के लिए नई रणनीति तैयार की है।

योजना के अनुसार गेहूं की फसल कटते ही खेतों में हरे चारे की विशेष व्यवस्था की जाएगी और किसानों द्वारा लगाई गई अस्थायी बाड़ हटाकर नीलगायों को आकर्षित किया जाएगा। इसके बाद उन्हें बोमा क्षेत्र तक लाकर पकडऩे का प्रयास किया जाएगा। किसानों का कहना है कि जब तक जमीन पर असरदार और वैज्ञानिक योजना लागू नहीं होगी, तब तक नीलगायों से होने वाले नुकसान पर रोक लगाना मुश्किल है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर एक साल की तैयारी और बड़े अभियान के बाद यदि केवल चार नीलगाय ही पकड़ी जा सकीं, तो पूरी रणनीति की जवाबदेही कौन तय करेगा?

75 इमरजेंसी कॉल बॉक्स में कई बंद, मुसीबत में लोगों को नहीं मिल रही मदद

मेंटेनेंस के अभाव में स्मार्ट सिटी की व्यवस्था बेअसर- अधिकारियों को भी नहीं पता कितने चालू और कितने बंद

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में आपात स्थिति के दौरान तत्काल सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगाए गए इमरजेंसी कॉल बॉक्स अब खुद मदद के मोहताज नजर आ रहे हैं। शहर के करीब 75 स्थानों पर लगाए गए इन कॉल बॉक्स में से कई बंद पड़े हैं, जिससे दुर्घटना, बीमारी या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

हैरानी की बात यह है कि शहर में कितने कॉल बॉक्स चालू हैं और कितने बंद, इसकी स्पष्ट जानकारी स्मार्ट सिटी अधिकारियों के पास भी नहीं है। ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च कर स्थापित की गई यह व्यवस्था अपनी उपयोगिता खोती दिखाई दे रही है। सड़कों पर लगे कई कॉल बॉक्स अब सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं।

जानकारी के अनुसार स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगाए गए इन कॉल बॉक्स की निगरानी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाती है। किसी भी आपात स्थिति में व्यक्ति को केवल बॉक्स का बटन दबाकर माइक्रोफोन के माध्यम से अपनी समस्या बतानी होती है। इसके बाद कंट्रोल रूम से संबंधित विभाग, पुलिस या एम्बुलेंस को सूचना भेजी जाती है। लेकिन नियमित रखरखाव नहीं होने और लोगों में जागरूकता की कमी के कारण इस सुविधा का उपयोग लगभग नगण्य है। पिछले दो वर्षों में गिने-चुने लोगों ने ही इन कॉल बॉक्स का इस्तेमाल किया है। जबकि इस दौरान शहर में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनीं, जब यह सुविधा उपयोगी साबित हो सकती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय-समय पर मेंटेनेंस किया जाए और इनके उपयोग को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, तो यह व्यवस्था सड़क पर संकट में फंसे लोगों के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकती है। फिलहाल स्मार्ट सिटी की यह महत्वाकांक्षी योजना उपेक्षा के कारण दम तोड़ती नजर आ रही है।

आज से फिर गूंजेंगी शहनाइयां, शुरू होंगे मांगलिक कार्य

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। ज्येष्ठ अधिकमास की समाप्ति के साथ ही आज से विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण सहित सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। करीब एक माह तक शुभ आयोजनों पर लगी विराम की स्थिति समाप्त होने के बाद शहर में एक बार फिर शादी-ब्याह और धार्मिक आयोजनों की रौनक लौटने लगी है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अधिकमास समाप्त होने के साथ ही शुभ मुहूर्तों का क्रम शुरू हो गया है। इसके चलते विवाह स्थलों, मैरिज गार्डनों, बैंड-बाजों, कैटरिंग और सजावट व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी उत्साह है। आने वाले दिनों में शहर में बड़ी संख्या में वैवाहिक और धार्मिक आयोजन होने की संभावना है। इसी क्रम में आज 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यह दिन सोना-चांदी, आभूषण, वाहन, भूमि-भवन और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। खास बात यह है कि इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ सर्वार्थसिद्धि योग भी बन रहा है, जिससे शुभ कार्यों का महत्व और बढ़ गया है। ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि गुरु पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना जाता है। इस योग में की गई खरीदारी और निवेश लंबे समय तक सुख-समृद्धि देने वाले माने जाते हैं। यही वजह है कि व्यापारी वर्ग भी इस दिन विशेष तैयारियों में जुटा है। अधिकमास की समाप्ति और शुभ योगों के कारण आज से शहर में मांगलिक आयोजनों और खरीदारी गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।

वर्षा काल में बाढ़ और अतिवृष्टि से उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। एडीएम श्री अत्येन्द्र सिंह गुर्जर के द्वारा जिले में वर्षा काल में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण एवं जनमानस कि सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने के आदेश जारी कर दिए गए है। आदेश के अनुसार कंट्रोल रूम की स्थापना प्रशासनिक संकुल भवन के भू अभिलेख कार्यालय के अधीक्षक भू अभिलख के कक्ष में की गई है।

कंट्रोल रूम का फोन नं. (0734-2513512) है। उल्लेखनीय है कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष आगामी 15 अक्टूबर तक 24*7 प्रभावशील रहेगा। कंट्रोल रूम के नायब तहसीलदार श्री माधव प्रसाद मोंगरे होंगे। नियंत्रण कक्ष में शिफ्ट के अनुसार कर्मचारियों की ड्युटी लगाई गई है जो उपरोक्त फोन नंबर पर 24 घण्टे उपलब्ध रहेंगे और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सुचना मिलने पर उसे पंजी में दर्ज कर प्रभारी श्री माधव प्रसाद मोंगरे नायब तहसीलदार (9424697204) और संपुर्ण जिले में नोडल अधिकारी के रूप में समन्वयक श्री संतोष कुमार जाट डिस्ट्रीक्ट कमाण्डेन्ट होमगार्ड (9926769808) को अवगत करायेंगे।

सुबह गले में डाला फंदा, शाम को कटी हाथ की नस

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रेम विवाह करने वाली महिला ने सुबह फांसी लगाने का प्रयास किया पति ने उसे बचा लिया, लेकिन शाम को उसने हाथ की नस काट ली। पति ने उसे उपचार के लिये चरक अस्पताल में भर्ती कराया है।

इंदौर-नागदा बायपास मार्ग हाटकेश्वर कालोनी में रहने वाली दीक्षा पति पार्थ नागर 21 साल को नीलगंगा थाना पुलिस की डायल 112 चरक अस्पताल लेकर पहुंची थी। दीक्षा के एक हाथ की नस कटी थी और कलाई पर कई गहरे जख्म थे। आपरेशन थियेटर में सर्जरी के बाद उसे उपचार के लिये भर्ती किया गया है। पति पार्थ ने बताया कि वह ट्रेवल्स का काम करता है। 3 साल पहले प्रेम विवाह किया था, 8 माह का बेटा है, दीक्षा जयपुर की रहने वाली है। सुबह उसने फांसी लगाने का प्रयास किया था, उस वक्त भी डायल 112 बुलाई गई थी। पुलिस समझाईश के बाद दीक्षा का गुस्सा कम हुआ था, उसकी हरकतों को देखते हुए पुलिस कंट्रोलरूम पहुंच शिकायती आवेदन भी दिया। लेकिन शाम को उसने ब्लेड से हाथ की नस काट ली। जानकारी यह भी सामने आई कि पार्थ रातभर घर नहीं लौटा था दीक्षा को उस पर दूसरी महिला के संपर्क में होने की शंका है। जिसके चलते दोनों के बीच आये दिन विवाद होते रहते है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक ने लगाई फांसी

पत्नी और सास से था प्रताड़ित, 6 पेज का मिला सुसाइड नोट

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक ने शादी के चार माह बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 6 पेज से अधिक का सुसाइड नोट लिखा है। जिसमें पत्नी और सास पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं।

आगर जिले के नलखेड़ा में रहने वाला राहुल पिता रामकरण सूर्यवंशी 27 साल यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। 10 फरवरी को उसकी मन्नत उर्फ कविता से शादी हुई थी। शादी के बाद वह यूपीएससी की पढ़ाई के लिए उज्जैन स्थित नागझरी क्षेत्र की न्यू इंदिरा नगर कॉलोनी में किराए से रहने आ गया था। सोमवार दोपहर दोस्त घर पहुंचा तो राहुल ने दरवाजा नहीं खोला। खिड़की से देखने पर राहुल फंदे पर लटका दिखाई दिया। दोस्त सुभाष ने पुलिस को सूचना दी और खिड़की तोड़कर फंदे शव को नीचे उतारा। राहुल ने फांसी लगाने से पहले नई रस्सी खरीदी थी यही नहीं उसने 6 पेज से अधिक का सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें चार माह की शादी की पूरी दास्ता लिखी गई थी। राहुल पत्नी कविता उर्फ मन्नत और उसकी मां सिद्दीका कामरिया की प्रताड़ना परेशान था। सुसाइड नोट में लिखा गया कि वह दहेज लेने के खिलाफ था शादी के समय ससुराल वालों से साफ मना कर दिया था। 2027 में आईएएस बनने का सपना था। लेकिन शादी के चार दिन बाद ही सास सिद्दीका ने सोने की चेन उपहार में दी और कुछ दिन बाद ही वापस मांग ली। शादी के बाद पत्नी मायके चली गई और वह पढ़ाई के लिए उज्जैन आ गया लेकिन सास उसे फोन पर प्रताड़ित करने लगी और तलाक देने का दबाव बनाने लगी। उसने एक व्यक्ति के माध्यम से झूठ तलाक के केस में फसाने का षड्यंत्र भी रचा था। राहुल ने सुसाइड नोट में शादी के चार माह की पूरी बातें लिखी और लिखा कि उसे समाज और न्यायालय से न्याय नहीं मिल पाएगा। सुसाइड नोट में पत्नी और सास का पता उज्जैन रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अगर लिखा गया है और दोनों के नंबर भी अंकित किए गए हैं। राहुल ने अपने माता-पिता से भी माफी मांगी है। नागझिरी पुलिस ने मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सोपा। सुसाइड नोट जप्त कर जांच शुरू की गई है।

शिप्रा नदी में डूबने से बिहार के युवक की मौत

उज्जैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। परिवार के साथ आस्था का नहान करने बिहार से आया युवक शाम को क्षिप्रा में डूब गया। परिवार की सूचना पर गोताखोरों ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ देर बाद उसका शव निकाला गया।

महाकाल थाना पुलिस ने बताया कि बिहार के ग्राम फूलवारिया महू जिला वैशाली से रोहित कुमार पिता राजकिशोर शाह 25 साल परिवार के साथ सोमवती अमावस्या होने पर आस्था का नहान और महाकाल दर्शन करने आया था। शाम 7 बजे के लगभग परिवार रामघाट पहुंचा था। परिवार डूबकी लगाकर बाहर आ गया था। लेकिन रोहित डूबकी लगाने के बाद वापस नहीं निकला। परिवार नहान के बाद कपड़े बदलने चैजिंग रूम चला गया। कुछ देर बाद रोहित दिखाई नहीं दिया तो उसकी तलाश शुरू की गई। उसके डूबने की आशंका सामने आते ही गोताखारों ने सर्चिंग अभियान शुरू किया। कुछ देर बाद उसे बाहर निकाला गया। इस दौरान एसडीआरएफ और होमगार्ड ने सीपीआर दिया, लेकिन सिर में चोंट लगी होने से उसकी मौत हो चुकी थी। आशंका जताई गई कि गोता लगाने के दौरान चोंट लगने पर डूबा था। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर रात में शव चरक अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष पहुंचाया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जायेगा।

निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानको का पालन किया जाए- संभाग आयुक्त श्री सिंह

संभाग आयुक्त ने सिंहस्थ 2028 के अंतर्गत प्रचलित निर्माण कार्यों की समीक्षा की

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। संभाग आयुक्त सह सिंहस्थ मेला अधिकारी श्री आशीष सिंह ने मंगलवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माणाधीन एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन विकास प्राधिकरण श्री संदीप सोनी, सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संभाग आयुक्त श्री सिंह ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाए।

सिंहस्थ 2028 के तहत निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में नगर निगम, उज्जैन विकास प्राधिकरण तथा उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा सिंहस्थ-2028 को दृष्टिगत रखते हुए किए जा रहे विभिन्न विकास एवं अधोसंरचना निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। संभाग आयुक्त श्री सिंह ने सभी विभागों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित तरीके से कार्य संपादित करने के निर्देश दिए।

उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा के दौरान संभाग आयुक्त सिंह ने विक्रम कीर्ति मंदिर एवं वीर भारत संग्रहालय के निर्माण एवं विकास कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि यह परियोजनाएं उज्जैन की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान से जुड़ी हुई हैं, अतः इनके निर्माण में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए तथा विशेषज्ञों की सतत निगरानी में कार्य पूर्ण कराया जाए।

बैठक में मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के आसपास संचालित निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। संभाग आयुक्त श्री सिंह ने निर्देश दिए कि वर्तमान वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। साथ ही निर्माण स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं तथा श्रमिकों एवं आमजन की सुरक्षा के लिए सभी निर्माण सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए।

उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन सिंहस्थ मेला कार्यालय की समीक्षा करते हुए संभाग आयुक्त ने निर्देश दिए कि यह भवन सिंहस्थ-2028 की व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण केंद्र होगा, इसलिए इसकी विशेष मॉनिटरिंग करते हुए उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यूनिटी मॉल परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की तथा कार्यों की गति बढ़ाकर परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मेला अधिकारी श्री सिंह द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वर्षा ऋतु के दौरान निर्माण कार्यों में अतिरिक्त सावधानी बरती जाए तथा सभी परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए।